04 - मनरेगा के नाम परिवर्तन का औचित्य

05 - कागजों पर बची शादी को बनाए रखना अनुचित

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 29 दिसंबर, 2025

06 - ऐतिहासिक भोजशाला में परंपरा अनुसार 5 दिवसीय भोज...

07 - जेएच कॉलेज में एसडीईआरएफ ने दिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 91, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

जो जीवन की धूल चाट
कर बड़ा हुआ है
तूफ़ानों से लड़ा और
फिर खड़ा हुआ है

जिसने सोने को खोदा
लोहा मोड़ा है
जो रवि के रथ का घोड़ा है

वह जन मारे नहीं मरेगा
नहीं मरेगा

जो जीवन की आग जला
कर आग बना है
फ़ौलादी पंजे फैलाए नाग बना है

जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है
जो युग के रथ का घोड़ा है

वह जन मारे नहीं मरेगा
नहीं मरेगा

– केदारनाथ अग्रवाल

प्रसंगवश

असम में हिंसा और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की मुश्किलें?

दिलीप कुमार शर्मा

साल 2016 में बीजेपी असम में ÷जाति, माटी, भेटी÷ अर्थात जाति, ज़मीन और मातृभूमि की रक्षा का वादा करके पहली बार सत्ता में आई थी। लेकिन यहां की जनजातियों में लगातार बढ़ रही नाराज़गी से इन नारों पर सवाल उठ रहे हैं। अगले चार महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले में हुई हिंसा की ताज़ा घटनाओं ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त क्षेत्र कार्बी आंगलोंग की हिंसा में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा में एक आईपीएस अधिकारी समेत 60 से ज़्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं। कई महिला पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। 25 साल के एक विकलांग व्यक्ति के घर में लगाई आग में वह ज़िंदा जल गए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग के घर को भी फूंक दिया। ज़िले में इंटरनेट सेवा बंद है। क्षेत्र में सेना ने गुरुवार को इलाके में फ़्लैग मार्च किया।

ऊपरी असम में बीते दो दशकों से पत्रकारिता कर रहे अवीक चक्रवर्ती मानते हैं कि पिछले कुछ समय से ख़ासकर ऊपरी असम के कई समुदायों में सरकार को लेकर नाराज़गी देखने को मिली है। ऊपरी असम के छह समुदाय अनुसूचित जनजाति की मांग पूरी नहीं होने से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में छह स्थानीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का साफ़ वादा किया था। हाल ही में चाय जनजाति समेत इन समुदायों के लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे थे। अब कार्बी आंगलोंग में हुई हिंसा और वहां की जनजाति की नाराज़गी ने परेशानी को और बढ़ा दिया है।÷

हाल ही में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया ज़िले में सैकड़ों लोग एसटी का दर्जा देने की मांग पर विरोध आंदोलन कर चुके हैं। जिसके बाद असम कैबिनेट ने राज्य के इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर मंत्रियों के समूह की एक रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। हालांकि दो दिन पहले मुख्यमंत्री सरमा ने मीडिया के सामने यह कह दिया था कि एसटी का दर्जा देने की प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी नहीं होगी। एसटी की मांग कर रहे आंदोलनकारी संगठन भी चुनाव से पहले एसटी का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। सीएम के इस बयान के बाद इन संगठनों ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

राज्य में उत्पन्न संकट की ऐसी स्थिति के बीच मुख्यमंत्री हिमंत ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के 24वें सर्ग का श्लोक 28 साझा किया। इस श्लोक ÷राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः....% का अर्थ है वह भयानक रूप वाला राक्षस यहां की प्रजा को हमेशा डराता रहता है। वरिष्ठ पत्रकार नव कुमार ठाकुरिया भयानक रूप वाले राक्षस वाली बात को यहां के बुद्धिजीवियों, लेखकों और पत्रकारों से जोड़कर देखते हैं। वह कहते हैं, ÷असल में कार्बी आंगलोंग की हिंसा के बारे में जिस कदर लिखा जा रहा है, उसमें कार्बी जनजाति का अस्तित्व मिट जाने की बात हो रही हैं।÷

असल में गुवाहाटी में शुरू हुए असम पुस्तक मेले में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री हिमंत ने बुधवार को कहा था कि आग बुझाने की अगर ताक़त न हो तो आग लगाने वाले लेख लिखने का भी अधिकार नहीं है। 2021 में राज्य के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाली मूल के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार बेदखली अभियान चलाया। इस तरह हज़ारों बीघा सरकारी ज़मीन ख़ाली करवाई। लेकिन कार्बी आंगलोंग में सरकारी तौर पर तय चारागाह आरक्षित भूमि और विलेज ग्रेजिंग रिज़र्व की ज़मीन ख़ाली करवाने की मांग ने सीएम हिमंत को परेशानी में डाल दिया है।

कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से कार्बी आंगलोंग की स्थिति को बल प्रयोग के बजाय संवेदनशीलता से संभालने की अपील की है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा जोरहाट से लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर लिखा ÷यह साफ़ है कि जब तक हिमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री रहेंगे, असम के मूल निवासियों, जातीय समुदायों, जनजातियों और स्थानीय लोगों की चिंताएं हमेशा दूसरे नंबर पर रहेंगी।÷

असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने कहा, ÷मुख्यमंत्री केवल चुनाव में वोट लेने की बात को ध्यान में रखकर ही कोई क़दम उठाते हैं। जब कोई संकट वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो वह समस्या से निपटने की बजाए अपने फ़ायदे के अनुसार काम करते हैं। इसलिए कार्बी आंगलोंग में आज ऐसी हिंसात्मक स्थिति पैदा हो गई है। जिस इलाके में हिंसा हुई है, वहां हिंदी बोलने वाली आबादी बसी है। पिछले लोकसभा चुनाव में सीएम ने हिंदी भाषी लोगों का समर्थन करते हुए उनकी समस्या को सुलझाने की बात की थी और बीजेपी जीत गई। इसके बाद जब कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद का चुनाव था तो कार्बी लोगों से वादा कर दिया कि सरकार गैर कार्बी लोगों से ज़मीन ख़ाली कराएगी। बीजेपी वह चुनाव भी जीत गई, लेकिन किसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया गया। इसलिए आज स्थिति हिंसा तक पहुंच गई है। कार्बी जनजाति के लोग 6 दिसंबर से भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। सीएम अब कह रहे हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए उस इलाके में बेदखली अभियान नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हिमंत की सरकार ने ऐसे कई बेदखली अभियान मुसलमान इलाकों में चलाए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा था।÷

लंबे समय तक कार्बी आंगलोंग ज़िले में काम कर चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता ने कहा, ÷असम को अशांत करने के इरादे से एक तीसरा पक्ष इस हिंसा को हवा दे रहा है। वरना आंदोलनकारी स्वायत्तशासी परिषद के प्रमुख का घर को क्यों जलाते? आंदोलनकारी जिस इलाके में वह बेदखली अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं वहां गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रोक का आदेश दे रखा है।÷

बीजेपी नेता कहते हैं, ÷किसी एक घटना को मुख्यमंत्री की कार्य दक्षता से जोड़ना उचित नहीं है। जहां तक कार्बी आंगलोंग की बात है तो अदालत का जो भी फैसला आएगा सरकार उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकार अनिर्बान रॉय कहते हैं, ÷जनजातियों की नाराज़गी वाजिब है। लेकिन अभी यह कहना कि इन मुद्दों की वजह से सीएम सरमा के लिए चुनाव कठिन हो जाएगा, जल्दबाज़ी होगी।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

ठंड का बढ़ गया कहर, कांप रहे गांव और शहर

● कश्मीर में पारा 0 डिग्री, राजस्थान में बढ़ गई ठिठुरन ● यूपी, बिहार से लेकर झारखंड तक मौसम का सितम

नई दिल्ली (एजेंसी)। रविवार को राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान 2.1 डिग्री, करौली में 2.4 डिग्री, सीकर में 3.5 डिग्री, पाली में 3.6 डिग्री और दौसा में 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिसार में तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के फरीदकोट में तापमान 3.4 डिग्री, पटियाला में 4.6 डिग्री और अमृतसर-लुधियाना में 4.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। दरअसल, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का असर है। ये जमीन से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं हैं। इस बार इनकी रफ्तार 262 किमी घंटा तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 23 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है, इसका असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर नजर आ रहा है। रविवार को 13 फ्लाइट रद्द की गई हैं। डीजीसीए ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक को फॉग विंडो घोषित किया है। इस दौरान कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। शीतलहर और कोहरे के चले सभी परिषदीय स्कूलों में 15 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। सभी शिक्षकों को 30 दिसंबर तक काम निपटाने का आदेश दिया गया है।

यूपी में 15 दिनों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित, ठंड ने कर दिया खेल

उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के शीतकालीन अवकाश की तैयारी शुरू कर दी है। सभी परिषदीय स्कूल 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। शिक्षकों को 30 दिसंबर तक अपने सभी विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, छुट्टियां 31 दिसंबर से प्रभावी हो रही हैं, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में पारा तेजी से गिरने और घने कोहरे के कारण शिक्षक संगठनों ने जल्द छुट्टी की मांग की थी। शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अपील की है कि बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए 29 और 30 दिसंबर को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर दिया जाए, ताकि छोटे बच्चों को राहत मिल सके। विभाग के आदेशानुसार, 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक छुट्टियां रहेंगी और इसके बाद 15 जनवरी से स्कूल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। यह शीतकालीन अवकाश केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी हर साल घोषित होने वाले नियमित कैलेंडर का हिस्सा है।

अब बंगाल में जन्म व जाति प्रमाणपत्र भी जांच के घेरे में

● डोमिसाइल प्रमाणपत्रों के बाद चुनाव आयोग ने बढ़ाई निगरानी

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल में जारी डोमिसाइल (घोषणा-पत्र) प्रमाणपत्रों के बाद अब चुनाव आयोग की जांच के घेरे में जाति और जन्म प्रमाणपत्र भी आ गए हैं। आयोग ने जाति व जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ा दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने राज्य सरकार से वर्ष 2011 के बाद से रद्द किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों की सूची तलब करने के साथ ही अब जिला प्रशासनों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने विशेष रूप से उन अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और जन्म प्रमाणपत्रों का ब्योरा मांगा है, जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के बाद से जारी किए गए हैं। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखित आदेश दिया है कि इस वर्ष 24 जून से 25 दिसंबर के बीच जारी किए गए सभी दस्तावेजों का डाटा विधानसभा क्षेत्र, माह और तारीख के अनुसार तैयार करके उसे भेजा जाए। आयोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जन्म प्रमाणपत्रों की जांच हाल में जन्मे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन वयस्कों के लिए है जिन्होंने विलंबित पंजीकरण के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।

3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ ट्रांसफर

रतलाम में सीएम ने पूर्व सांसद की प्रतिमा का किया अनावरण

रतलाम (नप्र)। रतलाम के जावरा में सीएम डॉ मोहन यादव ने राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। रविवार को शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय जावरा में सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

सीएम ने सुजापुर में पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण पांडेय की प्रतिमा अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर पांडेय ने गांव की माटी से निकल कर आदर्शवादी राजनीति के दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में इस क्षेत्र की भूमि को प्रकाशमान किया है।

उन्होंने कहा जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश एवं देश की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है। हम सभी डॉ. पांडेय के आदर्शों पर चलने का संकल्प ले।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के गांव सुजापुर में जावरा विधायक श्री राजेंद्र पांडेय एवं उनके परिवार द्वारा विकसित किए गए स्मृति कुंज में स्थापित मालवा के गांधी के नाम से सुविख्यात जावरा मंदसौर नीमच क्षेत्र के पूर्व सांसद स्व. लक्ष्मी नारायण पांडेय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया।जावरा क्षेत्र के विधायक श्री राजेंद्र पांडेय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं सभी अतिथियों को साफा पहनाकर पुष्प हारों से स्वागत किया। श्री पांडेय परिवार के सदस्य गणों ने भी अतिथियों का आतमीय स्वागत किया।पूर्व सांसद स्व. लक्ष्मी नारायण पांडेय एवं जावरा के विधायक श्री राजेंद्र पांडे के गृह गांव सुजापुर में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, मंदसौर जावरा नीमच क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, श्री हितानंद शर्मा, विधायक श्री राजेंद्र पांडे, जावद विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा, नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक श्री अनिरुद्ध मारू, सुवासरा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्री मथुरा लाल डामोर, पूर्व विधायक श्री श्री यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जनप्रतिनिधि गण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री महेश सोनी ने किया। श्री प्रदीप उपाध्याय ने आभार माना।

हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयरस्ट्रिप बना रहा भारत

● अमेरिकी मीडिया का दावा-गलवान झड़प के बाद निर्माण ● बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी, चल रही तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत हिमालयी इलाके में चीन से होने वाली किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इस कदम की शुरुआत हुई थी। उस झड़प ने 2200 मील लंबी बॉर्डर पर भारत की सामान पहुंचाने की व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) की बड़ी कमियों को उजागर किया था। दशकों से चीन ने अपनी बॉर्डर पर रेल और सड़कों का विशाल नेटवर्क बनाया है। जबकि भारत अपने पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पीछे रह गया।

चीन घंटों में मदद पहुंचाता है, भारत को हफ्ते लगते हैं- 2020 की झड़प के दौरान, 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय और चीनी सैनिक डंडों और कांटेदार तारों से लिपटे क्लबों से हाथापाई कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन मजबूत कनेक्टिविटी की वजह से कुछ ही घंटों में मदद पहुंचा सकता था। जबकि भारत को उस इलाके की खराब या नहीं के बराबर सड़कों से एक्स्ट्रा सैनिकों को पहुंचाने में एक हफ्ते का समय लगता। लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में पूर्व ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर जनरल अमृत पाल सिंह ने कहा- इस घटना के बाद हमें अपनी पूरी रणनीति बदलने की जरूरत महसूस हुई। **11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही जोजिला सुरंग-** सबसे जरूरी प्रोजेक्ट में से एक जोजिला सुरंग है, जिसे उत्तरी भारत के पहाड़ों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा।

सीमा चौकियों तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा

जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लगभग 9 मील (15 किमी) लंबा यह प्रोजेक्ट लद्दाख में बॉर्डर चौकियों तक सामान पहुंचाने के मुश्किल काम को आसान बना देगा। लद्दाख में भारी बर्फबारी के कारण ये चौकियां साल में 6 महीने तक सप्लाई लाइन से कटी रहती हैं। फिलहाल सामान ट्रकों या ट्रेनों से जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी डिपो तक पहुंचाया जाता है। वहां से सेना के काफिले उन्हें लद्दाख की राजधानी लेह तक ले जाते हैं। लेह से छोटी गाड़ियां खराब रास्तों से गुजरती हैं और फिर पोर्टर (सामान ढोने वाले लोग) और खच्चर समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 25 °c | न्यूनतम 22°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 29 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए

- शिवराज बोले-मैं भी एक सीख रहा हूं,इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी

चेन्नई (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे खुद भी किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान शनिवार को तमिलनाडु के होसुर में आयोजित मेगा किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम सद्गुरु जग्गी वासुदेव

के ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान शिवराज ने कहा कि भारत की भाषाई विविधता हमारी ताकत है और एक-दूसरे की भाषाएं सीखने से राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ मजबूत होती है। चौहान ने कहा कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव के अनुभवों से प्रेरित होकर सरकार वृक्ष आधारित कृषि को लेकर एक नई नीति बनाने पर काम करेगी। ईशा फाउंडेशन पहले से ही इस दिशा में काम कर रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ईशा फाउंडेशन किसानों के बीच पेड़ आधारित खेती को बढ़ावा दे रहा है।

भारत में इस्लामी राज की साजिश रच रहा अल-कायदा

भारत में इस्लामी राज की साजिश रच रहा अल-कायदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आतंकी संगठन अल-कायदा अफगानिस्तान को आधार बनाकर भारत में कट्टर इस्लामी शासन व्यवस्था लागू करने के मंसूबे बना रहा है। इस सिलसिले में अल-कायदा ने अफगानिस्तान में डिजिटल कमांड स्थापित कर रखा है, वहीं से वह भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन करता है। यह जानकारी महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते

(एटीएस) की जांच में सामने आई है। महाराष्ट्र एटीएस ने अल-कायदा से जुड़े जुबैर हंगारगेकर को गिरफ्तार कर उससे लंबी पूछताछ की है। जुबैर अल-कायदा के गहरे प्रभाव में था और वह भारत में संगठन का नेटवर्क तैयार करने में जुटा था। जुबैर के पास से बरामद कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पता चला कि अल-कायदा भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के विस्तार की साजिश पर कार्य कर रहा है। वह भारत में इस्लामी कानून वाली सरकार (खलीफा राज) की स्थापना के मंसूबे बांध रहा है। एटीएस की जांच में यह पता चला है।

मामले की जांच इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) भी कर रही है। जुबैर ने कट्टरपंथी विचारधारा के विकास के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लोगों से संपर्क किया। इनमें से कुछ को भड़काऊ साहित्य भी भेजा गया और उन्होंने विचारधारा को फैलाने का आश्वासन दिया था। अब ऐसे लोगों के बारे में जानकारियां जुटाने में एजेंसियां लगी हुई हैं।

सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता और मितव्यता का संदेश देने का प्रभावी माध्यम: मुख्यमंत्री

सोलह संस्कारों में पाणिग्रहण संस्कार का है विशेष महत्व,फिजूल खर्ची रोककर बच्चों को पढ़ाए लिखाए

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में पाणिग्रहण संस्कार का विशेष महत्व है। यह संस्कार ही परिवार परंपरा की निरंतरता का आधार बनता है। पाणिग्रहण संस्कार का संतों के सानिध्य और सामूहिक विवाह के आनंद के साथ संपन्न होना विशेष संयोग और सौभाग्य का प्रतीक है। सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक विभेद और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों की जगह सामाजिक समरसता और मितव्यता का संदेश देने का प्रभावी माध्यम हैं। समाज में सभी को ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान देना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने डॉक्टर बेटे का

विवाह सामूहिक विवाह समारोह में ही किया। बिना ऊंच-नीच और जात-पात के भेद के होने वाले सामूहिक विवाह समारोहों का आनंद अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हम विवाह और मृत्यु भोज जैसे आयोजनों में फिजूल खर्ची को रोककर अपनी बचत और संसाधनों का उपयोग बच्चों को पढ़ाने-लिखाने और परिवार की बेहतरी में करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपस्थित जनसमुदाय को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर जिले के क्षिप्रा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सह 251 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्प वर्षा कर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की मंगलकामना के साथ ईश्वर से नव विवाहितों को वैभव, यश, कीर्ति, और आनंद प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नव विवाहित जोड़ों से माता-पिता की सेवा करने और समाज के कल्याण में योगदान देने का आहवान भी किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में नव विवाहित जोड़ों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

सामूहिक विवाह से फिजूलखर्ची बचती है

समारोह में कथा वाचक उत्तम स्वामी जी ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव भी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों से फिजूलखर्ची रूकती है और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने बेटे का विवाह सामूहिक आयोजन में कर पूरे प्रदेश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक एवं श्री हेमंत खंडेलवाल सहित श्री हितानंद शर्मा और बड़ी संख्या में नव विवाहित जोड़ों के परिजन उपस्थित रहे।

सिंधु से जुड़े प्रोजेक्ट में तेजी आने से छटपटाया पाकिस्तान

- भारत के खिलाफ यूएनएससी को लिखी चिट्ठी, मांगी मदद

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद भारत जम्मू-कश्मीर में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लिए काम में तेजी ला रहा है। इसके लिए क्लीयरेंस जल्दी

दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अभियान तेज कर रहा है।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी लिखकर भारत पर समझौते को रोककर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि लाखों पाकिस्तानियों पर इससे मानवाधिकार और खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है। 11 दिसंबर को यूएनएससी अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को भेजे गए एक संदेश में पाकिस्तान ने भारत के फैसले का विरोध किया। पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने संधि के निलंबन के बाद भारत पर पानी को लगातार हथियार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

- **नॉन नेविगेशन इस्तेमाल पर कन्वेंशन शामिल**- पाकिस्तान का यह भी दावा है कि पहलगाम हमले के बहाने पर भारत ने समझौते को एकतरफा सस्पेंड कर दिया और यह कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जिसमें इंटरनेशनल वॉटरकोर्स के नॉन-नेविगेशनल इस्तेमाल पर यूएन कन्वेंशन भी शामिल है। यह चेतावनी दी गई है कि यह कदम एक परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है, जिससे देश रणनीतिक या राजनीतिक उद्देश्यों को छिपाने के लिए बदले हुए हालात के आधार पर संधियों से बाहर निकल सकते हैं। पाकिस्तान अपने मामले को मजबूत करने के लिए पांच एक्सपर्ट्स और स्पेशल रैपोर्टर्स के हालिया लेटर पर भी भरोसा कर रहा है।

'नई धार' के साथ उतरेगा जनसुराज

प्रशांत किशोर ने जनता का दिल जीतने का बनाया प्लान!

पटना (एजेंसी)। बिहार चुनाव में जनसुराज की हार के साथ प्रशांत किशोर को झटका जरूर लगा है, पर उनके राजनीतिक चिंतन को विराम नहीं मिला है। बिहार की भूमि से राजनीति का शीर्ष पाना आज भी टारगेट बना हुआ है। यह प्रशांत किशोर ने तमाम सांगठनिक ढांचा को भंग कर बता

दिया है। सामने कोई चुनाव नहीं है। इसलिए इस खास समय हड़बड़ी वाला संगठन खड़ा नहीं होगा, बल्कि नए कलेवर में समर्पित और विश्वसनीय कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की जाएगी। एनडीए की बंपर जीत के बाद बिहार में विपक्ष काफी कमजोर फोर्स बन गया है। राजद के युवराज तेजस्वी यादव विधायकों की संख्या बल के कम होने से काफी हताश भी है।

कर्नाटक में बुलडोजर नीति मुस्लिमों के घर तोड़े गए

- केरल सीएम बोले-बीजेपी की राह पर चल रही है कांग्रेस
- डीके शिवकुमार ने कहा-बाहरी नेता मामले में दखल न दें

बेंगलुरु (एजेंसी)। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना बीजेपी से की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा- कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपनाई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पिनाराई विजयन के कमेंट को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि 'बुलडोजर जस्टिस' और कानून के तहत गैर-कानूनी कब्जे हटाने में फर्क है। विजयन की आलोचना में हालात की सही समझ नहीं दिखती। उन्होंने कहा- बेंगलुरु के येलहंका के पास कोगिलु लेआउट में कचरा डंपिंग स्थल पर लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जो रहने योग्य नहीं है। कई नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। प्रभावित लोगों के

लिए अस्थायी ठहरने, खाने और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि संघ परिवार की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भी अपना रही है।

दिग्विजय सिंह को मिला शशि थरूर का साथ

कांग्रेस संगठन और अनुशासन के मुद्दों पर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस के संगठन में कमजोरी को सामने लाने और बीजेपी-आरएसएस संगठन पर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा की है। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं लेकिन तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है।

शशि थरूर ने कहा है कि किसी भी पार्टी में अनुशासन जरूर होता है। दरअसल, कांग्रेस सांसद और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई है। शशि थरूर ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो। हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह खुद इस बारे में बोल सकते हैं। हालांकि, बीजेपी-आरएसएस के संगठन से सीखने की बात पर शशि थरूर ने अलग रुख अपनाया है। शशि थरूर ने इस मामले में कहा,हमारा 140 वर्षों का इतिहास है, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम स्वयं से भी सीख सकते हैं।

बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में सेना ने बढ़ा दी गश्त

- कड़ाके की ठंड में भी जम्मू-कश्मीर में सेना का ऐक्शन

30-35 पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश,अभियान तेज

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड और 40 दिन की चिल्लई कलां के बावजूद सुरक्षाबलों ने किश्तवाड़ और डोडा जिलों में आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बर्फ से ढंके ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। खुफिया आंकलन के अनुसार जम्मू क्षेत्र में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। लगातार सर्चिंग और स्थानीय समर्थन कमजोर पड़ने के कारण ये आतंकी आबादी से दूर मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सेना ने अस्थायी बेस, निगरानी पोस्ट और गश्ती ग्रिड बनाकर ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में नियमित पेट्रोलिंग शुरू की है। पहले

सर्दियों में आतंकी गतिविधि कम होती थी।

- **80 से ज्यादा गांवों में भी सर्च ऑपरेशन जारी**-सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस पिछले 10 दिन से संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह सर्चिंग बॉर्डर एरिया के 80 से ज्यादा गांवों में चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकी संगठन घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। पिछले माह बीएसएफ के अधिकारी ने खुलासा किया था कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान झेलने के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर 72 पैड सक्रिय कर दिए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर में की यात्रा

- ऐसा करने वाली दूसरी प्रेसीडेंट,इससे पहले डॉ. कलाम सबमरीन में बैठे थे

कारवाड़ (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर पनडुब्बी (सबमरीन) में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वाघशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची। एम 75 स्कॉर्पीन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी वाघशीर को जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने इस साल राफेल की सवारी की थी। डॉ. कलाम 13 फरवरी 2006 को ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत विशाखापट्टनम में सबमरीन में कुछ घंटों के लिए बंगाल की खाड़ी में रहे। उनके साथ तत्कालीन नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश भी थे।

परिक्रमा

अभ्युदय मध्यप्रदेश का आगाज करते शाह और मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

अरुण पटेल

लेखक
सुबह सवेरे के
प्रबंध संपादक हैं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ग्रोथ समिट की नींव रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि मध्यप्रदेश में रुपया बोकर करोड़ों कमाये जा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश से अभ्युदय मध्यप्रदेश का आगाज किया। दूसरी ओर कांग्रेस पांच जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान के तहत सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने वाली है। इस प्रकार एक ओर जहां अमित शाह मध्यप्रदेश से कांग्रेस का बचा-खुचा जनाधार छीन कर भाजपा की झोली में डालने के लिए कृत संकल्पित हो गये हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मनरेगा को मुद्दा बनाकर गरीब मजदूरों को अपने साथ जोड़कर अपने खिसकते जनाधार को मजबूती देने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह समिट प्रदेश सरकार के संकल्प को आगे बढ़ायेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम् योगदान दे रहा है। राजमाता की नगरी और अटलजी की कर्मभूमि ग्वालियर से जो सौगात मिलने जा रही है वह वास्तव में साढ़े आठ करोड़ लोगों के लिए है। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 35 साल की नक्सल समस्या खत्म हो गयी है और इसी माह 11 दिसम्बर को लाल सलाम को अंतिम सलाम दिया गया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में 2.17 लाख करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक/निर्माण इकाइयों का भूमिपूजन किया। अमित शाह का जोर इस बात पर था कि मैन्यूफैक्चरिंग रिन्यूवल इनर्जी एग्री प्रोसेसिंग और आईटी व इंफ्रा स्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, इससे लगभग दो लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास का नया केन्द्र बन रहा है। मध्यप्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य इतना समृद्ध है कि यहां निवेश लाभदायक ही होगा। शाह ने उद्योगों व एमएसएमई

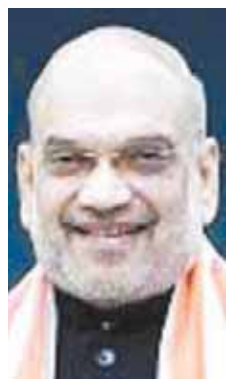

इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए 610 इकाइयों को 775 करोड़ रुपया निवेश प्रोत्साहन सहायता भी बांटी। कांग्रेस को निशाने ने पर लेते हुए शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में प्रदेश की गिनती बीमारु राज्यों में होती थी परन्तु भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने इस टेग को हटाकर राज्य को विकास की राह पर अग्रसर किया और अब मोहन यादव प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।

पांच जनवरी से कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर

कांग्रेस नये साल का आगाज 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान के रुप में करने जा रही है। यह ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यसमिति की तीन घंटे चली बैठक के बाद किया। उनका दावा था कि कृषि कानूनों की तरह मनरेगा को बचाने के लिए भी जन-आंदोलन होगा

और देश भर में रैलियां और जनसभायें आयोजित होंगी। कार्यसमिति की बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तेवर काफी तल्ख थे और उन्होंने सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अकेले ही इस योजना को खत्म कर दिया। बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की पहली बैठक में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को हर हाल में बचाने की शपथ ली। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हुए हमले की निंदा करते हुए खरगे ने कहा कि इससे भारत की छवि प्रभावित हुई है। एसआईआर प्रक्रिया पर उनका कहना था कि यह एक गंभीर मुद्दा है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करने का प्रयास है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए संगठन सृजन अभियान का तीसरा चरण नये साल के सूर्योदय के साथ करने जा रही है और यह अभियान एक जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें मंडल, पंचायत और वार्ड समितियों का गठन होगा। जब यह समितियां बन जायेंगी उसके बाद गांव चलो-बूथ चलो संपर्क कार्यक्रम चलाया जायेगा। इससे गांव से कार्यकर्ता बूथ, बूथ से मंडल, मंडल से ब्लाक और ब्लाक से जिला स्तर तक पहुंचेगे तथा पार्टी के कार्यक्रम के साथ भाजपा सरकार की असफलाओं पर भी चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम हर छः माह में आयोजित किया जायेगा। इसके साथ ही साथ मतदाताओं का सत्यापन भी किया जायेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने गांव-गांव चलाये जाने वाले कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की, उनका जोर इस बात पर था कि हमें आमजन से संपर्क बढ़ाना होगा, इसके लिए कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचें और वहां रात्रि विश्राम करें। लोगों को अपनी बात बतायें और उनकी बात सुने। भाजपा सरकार की असफलताओं को तथ्यों के साथ रखें, यह क्रम लगातार चलते रहना चाहिये, इस पर आमसहमति भी बनी।

और यह भी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर कराई जा रही है उसमें वोटों की चोरी प्रमाणित हुई है। भाजपा को जिन सीटों पर जितने मतों से जीत मिली है उन विधानसभा क्षेत्रों में उससे अधिक नाम हटाये गये हैं और ऐसा लगभग 60 सीटों पर देखने को मिला है जो यह स्पष्ट करता है कि 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने वोट चोरी के माध्यम से जीता है। न्यायालय में जाना है या नही, हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि सरकार ऐसे नहीं बनेगी। यदि प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकार बनाना है तो संगठन को बूथ स्तर तक जाना होगा तथा हर एक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुटना होगा।

हाई प्रोफाइल पार्टी के बीच पहुंची पुलिस ने म्यूजिक बंद कराया, 3 जगह कार्रवाई

टीआई ने सिंगर से माइक छीना, तेज म्यूजिक बजाने की शिकायत मिली

इंदौर। हाई प्रोफाइल पार्टी में अचानक पुलिस ने धावा दिया। म्यूजिक बंद हो गया और माइक टीआई ने ले लिया। समय के बारे में बताया और कहा इस फ्लोर को मैं सील कर रहा हूं। ग्राहकों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया और फ्लोर सील करवा दिया। कार्रवाई लसूड़िया पुलिस ने की है।

टीआई तारेश सोनी के मुताबिक स्कीम-78 स्थित 'द हब' बिल्डिंग में 'एफ बार' पर की। पुलिस को शिकायत मिली थी कि संचालक तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है, इससे रहवासियों को परेशानी होती है। शुक्रवार रात टीआई बल लेकर सीधे फ्लोर पर जा पहुंचे। उस वक्त पूरा फ्लोर भरा हुआ था। टेबल पर युवक युवतियां बैठी थी और लाइव म्यूजिक चल रहा था। पुलिसकर्मियों ने संचालक और मैनेजर को हिरासत में लिया। टीआई के मुताबिक पुलिस ने चार दिन पूर्व होटल, बार, पब, रेस्त्रां संचालकों को पुलिस कंट्रोल रुम बुलाकर समझाइश दी थी।

फ्लोर सील करने की घोषणा- टीआई ने सिंगर से माइक लिया और कहा यह ओपन फ्लोर है। ओपन फ्लोर में रात दस बजे के बाद म्यूजिक अलाउ नहीं है। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है। लेकिन वो बात स्पष्ट नहीं हो

रही है। इसका साउंड हमने चेक किया है। वृंदावन चौराहा से आगे तक आवाज आ रही है। पूरा रेडियस निकालो तो 500 मीटर का रेसियस आता है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। आज से यह फ्लोर सील कर रहे है। आज से आप टाइम का ध्यान रखेंगे। दस बजे का नियम है और अभी 10-50 हो रहे है। 50 मिनट ज्यादा हो गए है। इसके बाद पुलिस ने पूरा फ्लोर खाली करवा दिया। पुलिस यहां से की कीचन गई और म्यूजिक बंद करवा कर सील करने की कार्रवाई कर दी।

आरके क्लब पर एफआईआर

विजयनगर पुलिस ने आरके क्लब में नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर क्लब संचालक व मैनेजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। 25 दिसंबर की रात पुलिस टीम जब आरके क्लब पहुंची, तो पुलिस को देखकर संचालक ने बाहरी शटर पर ताला लगाकर क्लब बंद होने का दिखावा किया, जबकि अंदर गतिविधियां जारी थीं। पुलिस पहले से निगरानी कर रही थी। जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर क्लब संचालक मिथलेश कुमार व मैनेजर अमित कुमार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।

टुलुम रिसोर्ट पहुंची पुलिस

भंवरकुआं इलाके में पुलिस को शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी कि रिसोर्ट पर तेज आवाज में म्यूजिक और पार्टी चल रही है। सूचना के आधार पर रात 2 बजे पुलिस टीम पालदा स्थित टुलुम रिसोर्ट पहुंची, जहां जांच के दौरान कई युवक कमरों के अंदर पाए गए। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, रिसोर्ट के पास शराब पिलाने का वैध लाइसेंस नहीं था। मौके से साउंड सिस्टम और डीवीआर जब्त किए। मामले में रिसोर्ट मालिक केतन जैन, मैनेजर अजय और गोपाल के खिलाफ प्रिवेंटिव ऑर्डर के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने रिसोर्ट के कमरों की जांच कर वहां मौजूद युवकों को बाहर निकलवाया और उनके नाम-पते नोट किए। यह भी पता लगाया जा रहा है कि पार्टी किसने आयोजित की थी और किसके निमंत्रण पर लोग आए थे।

'व्यापम' के 12 मुन्ना भाइयों, फर्जी अभ्यर्थियों को पांच-पांच की साल

हाई कोर्ट ने इन सभी दोषियों को अर्थदंड की सजा भी दी

इंदौर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित और देश के सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में शामिल %व्यापम% के एक अहम मामले में शनिवार को इंदौर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। वर्षों पहले हुए इस घोटाले में परीक्षा देने वाले फर्जी अभ्यर्थियों, मुन्ना भाई और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 12 आरोपियों को पांच-पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की अदालत में सुनाया गया। सजा सुनाये जाने से पहले सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने माना कि आरोपियों ने संगठित तरीके से सरकारी परीक्षाओं की पवित्रता को भंग किया और योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन किया। गौरतलब है कि व्यापम घोटाला वर्ष 2013 में उजागर हुआ था, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया था। असली अभ्यर्थियों की जगह पैसे लेकर 'मुन्ना भाई' परीक्षा देते थे, वहीं कई बिचौलिये, दलाल और परीक्षा केंद्रों के कर्मचारी भी इस साजिश में शामिल पाए गए थे। इस घोटाले ने पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया था।

लंबी जांच और सुनवाई के बाद अब इस मामले में सजा सुनाए जाने को पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों को कानून किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

इंदौर। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई की। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 558 चालकों के चालान बनाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ भी विशेष मुहिम चलाई। प्रतिबंधित मार्गों पर चलने, वनवे उल्लंघन, ओवरलोडिंग, नो-पार्किंग और दस्तावेजों की कमी जैसे मामलों में 207 ई-रिक्शा और 39 ऑटो कुल 248 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। शहर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों और व्यस्त चौराहों पर नो-पार्किंग में वाहन खड़े कर ट्रैफिक बाधित करने वाले 139 वाहनों के चालान बनाए गए।

शातिर बदमाश भरत उर्फ भरतिया जिलाबदर

इंदौर। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शातिर बदमाश भरत उर्फ भरतिया पिता रामदास समिन्दर (उम्र 32 वर्ष), निवासी शीलनाथ कैम्प, परदेशीपुरा के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए जिलाबदर आदेश जारी किया।

पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम द्वारा उक्त आदेश क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सुनाया गया। साथ ही आरोपी, उसके परिजनों और क्षेत्र के रहवासियों को आदेश की जानकारी देकर पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

युवक ब्राउन शुगर लेकर घूमता मिला

इंदौर। ब्राउन शुगर लेकर ग्राहक की तलाश करते युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 1 लाख 10 हजार रुपए की 11.1 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। पूछताछ में पता चला कि वह अपना खर्चा चलाने मादक पदार्थ बेचता था। उससे मुख्य सरगना के खुलासे की भी संभावना है। पुलिस ने बताया कि देर रात 2 बजे सघन गश्त करते हुए एमआर-4 रोड पर एक्टिवा चालक को संदिग्ध रूप से घूमते देखा उसे रोका और पूछताछ की तो उसने अपना नाम शुभम उर्फ गुलशन पिता महेश यादव निवासी भागीरथपुरा होना बताया।

नववर्ष के पहले गुंडों पर पुलिस का डंडा, 377 पर कार्रवाई की

वांछित 126 से ज्यादा के वारंट को तामिल कराया गया

इंदौर। नववर्ष के पहले अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान अंतर्गत 377 बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। इस दौरान कई गुंडे बदमाशों को पुलिस ने कड़ी हिदायत दी कि नववर्ष की मस्ती में विघ्न डाला तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

शहर के चारों जोन के डीसीपी नेतृत्व में 26-27 दिसंबर की दरमियानी रात्रि 8 से 2 बजे तक फोर्स ने सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे-बदमाशों पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए पेट्रोलिंग की। इस दौरान 950 बदमाशों को चेक किया गया। विभिन्न प्रकरणों में वांछित कुल 126 से ज्यादा के वारंट को तामिल कराया। ड्रिंक एंड ड्राइव में 163 वाहन चालकों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई। मादक पदार्थ का सेवन करने पर 7 पर एनडीपीएस का केस दर्ज किया है। धारा 170 में 20, धारा 129 में 3, धारा 126 बी/135(3) में 22, धारा 141-1 ख में 28 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग कर की चैकिंग करते हुए क्षेत्र के 186 गुंडे/बदमाशों, 94 नकबजनों, 40 लुटेरों, 92 चाकूबाजों, 121 निगरानीशुदा बदमाश और 40 जिलाबदर-रासुका के बदमाशों तथा महिला संबंधी अपराधों एवं वाहनों में आगजनी व तोड़फोड़ में संलिप्त अपराधियों सहित करीब कुल 573 से ज्यादा बदमाशों को चेक कर कार्रवाई और आगे कोई अपराध ना करने की हिदायत दी गई। लगातार अपराधिक वारदातों में लिप्त बदमाशों के डोजियार फार्म भराए गए, ताकि वे दोबारा अपराध नहीं कर पाएं।

'एजु मीट' में शैक्षणिक क्रांति को मुस्लिम तरक्की का रास्ता बताया

(जावेद आलम)

इंदौर। मुसलमानों को प्रकृति ने सबसे ज़्यादा दिया, पर वह आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके कर्म भी ठीक नहीं हैं। विरोधी उन्हें लूटने के लिए एकजुट हैं और दुनिया के अधिकतर मामलों उनके हाथ में हैं। ऐसे में उन्हें हमख़याल लोगों के साथ मिलकर शिक्षा के अलावा विभिन्न मोर्चों पर सतत काम करना होगा। 'एक शाम फ़िक्रे उम्मत के नाम' से आयोजित तालीमी जलसे में यह बातें कही गईं।

बुज़ुर्ग धार्मिक विद्वान कमरुज्जमा आजमी (लंदन) ने ज्ञान आधारित क्रांति

● 'एक शाम फ़िक्रे उम्मत' आयोजित तालीमी जलसे में उद्गार

को मुसलमानों की समस्याओं का हल बताते हुए कुरान की शिक्षा आम करने की सलाह दी। उनके मुताबिक़ तलवार नहीं आचार, व्यवहार और ज्ञान की ताक़त ने इस्लाम को दूर-दूर तक फैला दिया। उन्होंने ग़ज़ा, बर्मा और फिलिस्तीन के हालात को ठोकर बताते हुए कहा कि जिस दिन हम न्याय, ज्ञान और उच्च चारित्रिक आदर्शों को अपना लेंगे, उस दिन हम दुनिया को बदल कर रख देंगे।

ब्रिटिश पॉलिटिकल कन्सल्टेंट, सीनियर सिविल सर्वेंट व चैरिटी डायरेक्टर डॉ वकार आज़मी ने अपने उद्बोधन में चिंता जताते हुए कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत ख़राब है। उन्हें दिखावे की आज़ादी मिली है। विरोधियों का कंट्रोल सीधा नहीं है फिर भी हर जगह उन्हीं की हुक्मरानी है। पूरी दुनिया में यही स्थिति है। उनके मुताबिक कुदरत ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रदान किया। धरती, धन, पॉवर सब है, पर हम निरर्थक व असंवेदनशील जीवन गुजार रहे हैं। संसाधन हमारे, पर कब्जा दूसरों का है। यहां तक कि क़ानून, इंटरनेशनल कोर्ट तक उन्हीं के हैं।

विभिन्न सामाजिक व शैक्षणिक संगठनों से जुड़े बैरिस्टर वकार आज़मी ने चिंता जताई कि विरोधी हमें लूटने के लिए एकजुट हैं। वह बहुत शातिराना ढंग से हमारी निजी बुराई को धर्म से जोड़ देते हैं। पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रखा है। ऐसे में हमारा रोल क्या है, हम क्या कर रहे हैं? जबकि हमारी कश्ती में तूफान आ गया। हम घेटोइज़्म का शिकार हो रहे हैं। हालात से निकलने का रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा अल्लाह ने तीन स्ट्रेटजी बताई हैं। अल्लाह की तरफ़ बुलाएं, ज्ञानार्जन पर ध्यान दें और नेकी के साथ चलें।

उन्होंने पैगंबर हज़रत मुहम्मद के जीवन से उदाहरण देते हुए बताया कि आप सल्ल ने जब लोगों को इस्लाम की ओर बुलाया तो करीबी लोगों ने फ़ौरन उनकी बात पर विश्वास करते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसकी वजह है आप सल्ल का उत्तम चरित्र। फिर चंद सालों में ही इस्लाम सब दूर फैलने लगा। यह सिलसिला अभी भी जारी है। हमें भी अपने कर्म उसी तरह के करने होंगे, तभी असर भी होगा। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के बीच उन्होंने कुरान की आयत सुनाई, 'ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है'। आयोजक संस्थानों में से एक सुन्नी वेलफेयर कौंसिल द्वारा इंदौर में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामकाज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि नौजवान अपने काम गंभीरता से करें तो इंक़लाब आ सकता है। शहर काजी डॉ. सैयद इशरत अली, मुफ्ती सैयद साबिर अली के अलावा शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, सुन्नी वेलफेयर कौंसिल व तैबा कॉलेज जैसे संस्थान क़ायम करने वाले मक़सूद गौरी ने भी संबोधित किया।

संपादकीय

दिग्विजय- निशाना किस पर?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की गई एक तस्वीर पर राजनीतिक हल्कों में बवाल मचा है। इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के साथ भाजपा में भी हुई है। सवाल उठ रहा है कि यह तस्वीर पोस्ट करने के पीछे दिग्विजयसिंह का मकसद क्या था? वो किस पर निशाना साध रहे थे? क्या यह कांग्रेस संगठन पर निशाना था अथवा पार्टी हाइकमान पर? यह तंज था या फिर कांग्रेस को नेक सलाह? बहरहाल दिग्विजयसिंह ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि चित्र बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने लिखा कि आरएसएस का ज़मीनी स्वयंसेवक और जनसंघ-बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जब पत्रकारों ने उनसे इस पोस्ट को लेकर सवाल किया कि क्या वो इसके जरिए कांग्रेस संगठन में सुधार चाहते हैं तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी का घोर विरोधी हूं। मैंने केवल उनके 'संगठन' की तारीफ़ की है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि चूंकि वे पूरे तरीक़े से संविधान और देश के क़ानून को नहीं मानते हैं, जो आरएसएस गैर रजिस्टर्ड संस्था है, जिस पर कोई क़ानून लागू नहीं होता है। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक मैं इसलिए हूं क्योंकि एक ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल क़िले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। हालांकि इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सिर्फ़ दिग्विजय सिंह ने ही राहुल गांधी की समझ पर सवाल नहीं उठाया है बल्कि बराक ओबामा ने भी इसका ज़िक्र किया है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर जो तस्वीर साझा की है वो तब की है, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस तस्वीर में एक सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी बीजेपी के तत्कालीन वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आगे और नीचे बैठे दिख रहे हैं। इसे साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा, कोरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का ज़मीनी स्वयंसेवक और जनसंघ, बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फ़र्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। इस पोस्ट से संदेश गया कि दिग्विजय सिंह ने इसके ज़रिये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी संगठन में बदलाव करने का मैसेज दिया है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से सफ़ाई के अंदाज में कहा कि उनका मक़सद कांग्रेस संगठन की आलोचना करना नहीं था, उन्हें जो कहना था वो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कह दिया है। मीडिया के इस सवाल कि क्या क्या कांग्रेस के संगठन की क्षमता उन्हें कम दिखाई दे रही है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है और हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से एक आंदोलन की पार्टी है। लेकिन अब किसी आंदोलन को वोटों में तब्दील करने में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। गौरतलब है कि बीते वैसे 19 दिसंबर को भी दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी से कहा था कि वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ कांग्रेस संगठन पर भी ध्यान दें। कांग्रेस को भी चुनाव आयोग की तरह सुधारों और व्यावहारिक विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है।

मनरेगा के नाम परिवर्तन का औचित्य

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

स्व. बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने पर एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी और जिस प्रकार उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में न्यायपालिका ने रिहा करने का आदेश दिया और कार्यवाही पर रोक लगाई, परंतु आज तक देश में महात्मा गांधी के खिलाफगंदी-गंदी टिप्पणी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कार्रवाई या दंड से विचार नहीं मरते। मैं चाहता हूं कि समाज के लोग आगे आकर ऐसे झूठे आरोपों का प्रतिकार कर सुनियोजित झूठ फैलाने वालों को तार्किक उत्तर देकर निरुत्तर करें। बाल ठाकरे की घटना का उल्लेख तो मैंने यह बताने के लिए किया है कि देश में दो प्रकार के कानून चलते हैं।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर श्वीबी - जी राम जी्य कर दिया है। संसद में प्रतिपक्ष दलों ने इस नाम बदलने का तीखा विरोध किया और जो होना स्वाभाविक भी था। भाजपा और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल 11 वर्षों से बल्कि अगर इतिहास में जाया जाए तो 1930 के बाद से ही महात्मा गांधी को बदनाम करने, उनका अपमान करने व उनके विरुद्ध अन्य प्रकार के झूठ फैला रही है और अब इन पिछले 11 वर्षों में इसमें ज्यादा गति आई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है। स्व. बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने पर एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी और जिस प्रकार उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में न्यायपालिका ने रिहा करने का आदेश दिया और कार्यवाही पर रोक लगाई, परंतु आज तक देश में महात्मा गांधी के खिलाफगंदी-गंदी टिप्पणी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कार्रवाई या दंड से विचार नहीं मरते। मैं चाहता हूं कि समाज के लोग आगे आकर ऐसे झूठे आरोपों का प्रतिकार कर सुनियोजित झूठ फैलाने वालों को तार्किक उत्तर देकर निरुत्तर करें। बाल ठाकरे की घटना का उल्लेख तो मैंने यह बताने के लिए किया है कि देश में दो प्रकार के कानून चलते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि संघ-भाजपा के लोग अभी तक ऊपरी तौर पर महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, परंतु उनके ही नीचे के अनुयायी महात्मा गांधी के खिलाफगंदे शब्दों के प्रयोग करते हैं। ऊपर से नमन और नीचे से कटन की यह संघ की शिक्षा है, इसके बहुत सारे प्रमाण मैं दे सकता हूं, परंतु अभी वह मेरा विषय नहीं है।

भाजपा के नेताओं और सत्ताधीशों के लिए शब्द कितने अर्थहीन हैं और केवल शब्दों तक सीमित हैं इसका प्रमाण उस दिन मिला जब संसद में उत्तर देते हुए कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में हैं। यह कितना विचित्र था कि जिनके दिलों में महात्मा गांधी हैं उनके कागजों से महात्मा गांधी हटाए जा रहे हैं। यह दिल, दिमाग और शब्दों की कागजों से दूरी शोध का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने के पीछे संघ के तीन उद्देश्य हैं-

1. एक वे देखना और तोलना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाने पर देश में क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उनका अगला चरण नोटों पर से भी गांधी का चित्र हटाने का हो सकता है। उन्हें अंतरमन से गांधी से इतनी घृणा है कि वह गांधी की हर याद को मिटाना चाहते हैं। यह प्रयोग उन्होंने सरकार बनने के बाद तब भी किया था जब केंद्र सरकार ने सफाई का अभियान चलाया था और जिन महात्मा गांधी ने 19वीं सदी के आरंभ से ही जब न संघ का जन्म भी नहीं हुआ था, न श्री मोदी का, तब सफाई का अभियान और संदेश दुनिया को दिया था। तब भी उसमें बापू का चित्र कहीं नजर नहीं आया केवल चश्मा रखा गया, ताकि कोई आरोप लगे तो कहा जाए कि हमने बापू का चश्मा लिया है।

2. दरअसल सरकार को मनरेगा के जो मूल प्रावधान थे उनमें ही परिवर्तन करना था क्योंकि मनरेगा जैसी योजना उनकी नीति के अनुकूल नहीं है। 2014 से 19 के बीच उन्होंने मनरेगा का बजट कम किया था, यहां तक कि काफी समय तक काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तक नहीं चुकी थी, फिर कई महीनों के बाद लाचार होकर लंबित राशि का एक हिस्सा जारी किया गया। हालांकि वह भी आवश्यकता के अनुसार और लंबित भुगतान के अनुसार पर्याप्त नहीं था। दरअसल मोदी सरकार इस योजना से मुक्ति चाहती है। इस योजना में जो संशोधित प्रावधान किए गए हैं वह बहुत ही चलाकी भरे और अप्रत्यक्ष रूप से कानून को अप्रभावी बनाने वाले हैं। जैसे यह कहा गया है कि सरकार ने कार्य दिवस बढ़कर वर्ष में 100 दिन से 125 दिन कर दिए हैं, परंतु इसके साथ यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि यह रोजगार उपलब्ध बजट के अनुसार ही दिए जाएंगे, यानी पहले मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन काम देने की सरकार को बाध्यता थी अब सीमा तो 125 दिन की गई है, परंतु बाध्यता नहीं है। जितना पैसा होगा उतने ही दिन काम दिया जाएगा और इसका अर्थ हुआ कि जब बजट नहीं मिलेगा तो काम नहीं मिलेगा। तथा अपने आप बाध्यता की बजाय योजना सरकार के मन पर निर्भर करेगी।

3. सरकार ने नाम बदलने और महात्मा गांधी के नाम की बजाय वीबी राम जी नाम करने के पीछे यह भी रणनीति दिखती है कि प्रतिपक्ष महात्मा गांधी के नाम को लेकर हल्ला गुल्ला करेगा, बहस करेगा, विरोध करेगा और हुआ भी तो भी उन प्रावधानों पर कोई चर्चा नहीं हो सकेगी, जो मनरेगा की मूल आत्मा और विचार को समाप्त करने वाले हैं तथा मौका पाकर भाजपा यह भी प्रचारित करेगी कि हमने तो राम का नाम जोड़ा है, प्रतिपक्ष राम को नहीं मानता इसलिए विरोध कर रहा है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष जाने अनजाने में भाजपा नेतृत्व के षड्यंत्र का शिकार हो गया।

अच्छा होता कि पहले उन प्रावधानों पर संसद में बहस होती जिनके माध्यम से मनरेगा कानून को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, देश की जनता इन तथ्यों को जान सकती। कृषि मंत्री श्री शिवराज जी ने संसद में उत्तर देते हुए कहा कि हमने श्रमिकों को मजदूरी के लिये देने की राशि डेढ़ लाख करोड़ रुपये कर दी है, परंतु किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि बजट तो मार्च में आना है उसके पहले आपने वृद्धि कैसे कर दी? तथ्य तो यह है कि लगभग 30000 करोड़ रुपए औजार आदि की खरीद और श्रमिकों की मजदूरी का पिछला बकाया है, जो अभी तक नहीं दिया गया। मैं मान लेता हूं कि मनरेगा के जो उद्देश्य थे उनमें कई कमियां सामने आई हैं, जैसे श्रमिकों को रोजगार के नाम पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों गांव के ताकतवर लोगों और कर्मचारियों ने मिलकर भारी भ्रष्टाचार किया है। बगैर काम के ही जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और दबंगों के गठजोड़ ने पैसा निकाल लिया है, परंतु यह दोष तो व्यवस्था का या तंत्र का है न कि कानून का। दूसरे चूँकि ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के लिए काम करने को मजदूर नही मिलते इसलिए अधिकारियों को मशीनों से कराना पड़ता है जो कि कानून के भावना और उद्देश्य के खिलाफहै।

अच्छा होता कि सरकार इन समस्याओं को तथ्यों सहित संसद में प्रस्तुत करती। हालांकि इन प्रक्रियाओं की त्रुटि का संबंध कानून के नाम से नहीं है। क्या वीबी रामजी के नाम हो जाने से ग्रामीण स्तर पर हो जाने वाला उपरोक्त भ्रष्टाचार रुक जाएगा? इसलिए नाम बदलने की अनुपयोगिता सरकार की मंशा और प्रतिपक्ष को बहिष्कार के लिए बाध्य कर उल्टे जाल में फंसने का षड्यंत्र स्पष्ट होता है। हालांकि प्रतिपक्ष की भी अनेकों कमियां हैं, जो न केवल राजनीतिक हैं, बल्कि महात्मा गांधी के प्रति उनकी निष्ठा के अभाव और दिखावे की प्रतीत होती हैं। राष्ट्रपिता के नाम को हटाना यह एक प्रकार से देश की सरकार पितृ हत्या की अपराधी है।

क्या यह उचित नहीं होता कि प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर लेकर समूचे भारत बंद का आह्वान करता और मैं दावे के साथ कहता हूं कि समूचे देश में इसका बहुत प्रभाव पड़ता और शहर कस्बे तो दूर गांव-गांव तक बंद रहते। परंतु प्रतिपक्ष ने भी इतनी बड़ी घटना को बहुत हल्के में लेने का अपराध किया है। कांग्रेस पार्टी की एक नेता के संसद समाप्ति के बाद स्पीकर के कक्ष में प्रधानमंत्री के साथ हंसते मुस्कुराते चाय पीते फोटो सारे देश ने देखे हैं। क्या इस फोटो में कहीं महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने की पीड़ा नजर आती है? क्या प्रतिपक्ष को उस दिन चाय पार्टी का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था? एक प्रतिपक्षी नेता उस दिन बीएमडब्ल्यू कंपनी के मुख्यालय में कार देख रहे थे, क्या यह राष्ट्रपिता के अपमान के प्रति गंभीरता का व्यवहार है?

मैं खेद के साथ यह लिखने को बाध्य हूं कि संघ-भाजपा महात्मा गांधी के नाम को हटाने की अपराधी है। और देश के मुख्य प्रतिपक्ष दल राष्ट्रपिता के अपमान को शाब्दिक व हल्केपन से लेने के अपराधी हैं।

इस तरह सिनेमा देखने की आदत डालनी होगी

संवैधानिक मूल्य

डॉ. मनीष जैसल

लेखक फिल्म समीक्षक और मीडिया प्राध्यापक हैं।

भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को सोचने और समझने का माध्यम भी है। देश में संविधान के लागू होने के बाद से ही फिल्मों ने हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारी नागरिक समझ को गहराई से प्रभावित किया है। भारत का संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानव गरिमा जैसे मूल्य इस बात का प्रमाण हैं कि हमारा समाज आदर्श समाज इन्हीं मूल्यों के आधार ही बन सकता है । यदि हम फिल्मों को भी इन्हीं संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से देखें, तो सिनेमा हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक सीख भी देता है और हमें बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। आजादी के तुरंत बाद बनाई गई फिल्मों में राष्ट्र निर्माण की भावना बहुत प्रबल दिखाई देती है। राज कपूर की फ़िल्म 'आवारा' सामाजिक असमानता और अन्याय की समस्या को सामने लाने का प्रयास करती हुई दिखती है । इस फिल्म में दिखाया गया कि अपराध किसी व्यक्ति के जन्म की वजह से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक हालात की वजह से पैदा होता है। वह दृश्य जब न्यायाधीश कहता है कि अगर बच्चे को गलत माहौल मिले तो वह अपराध की तरफ बढ़ सकता है, हमें बताता है कि संविधान का समान अवसर यानि समता का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है।

इसी तरह बिमल रॉय की फ़िल्म 'दो बीघा ज़मीन' (1953) आर्थिक असमानता के दर्द को बहुत सटीक ढंग से दिखाती है। किसान शंभू महतो का संघर्ष, अपनी जमीन बचाने के लिए रिक्शा चलाने को मजबूर होता है, हमें यह समझाता है कि गरीबी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की कमी का परिणाम है। यह फिल्म संविधान के आर्थिक न्याय की भावना को जीवंत रूप में दर्शाती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि विकास तभी सच्चा होता है, जब वह सबके लिए हो।

भारतीय सिनेमा में न्याय और नैतिकता की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति 'मदर इंडिया' (1957) में दिखाई देती है। जब राधा अपने बेटे बिरजू को गाँव की सुरक्षा और न्याय की रक्षा के लिए दंड देती है, तो यह दृश्य बताता है कि न्याय व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होता है। यह दृश्य दर्शकों को यह सिखाने का प्रयास करता है संविधान का मूल मूल्य न्याय है, और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का सम्मान जरूरी है।

1960 और 1970 के दशक में समाज में बदलाव की हवा तेज़ थी, और फिल्मों ने इन संघर्षों को आवाज़ दी। श्याम बेनेगल की फ़िल्म 'अंकुर' (1974) जातिगत शोषण और दमन के खिलाफ़ उठती नई आवाज़ का प्रतीक है। फिल्म के अंत में एक बच्चा जब मालिक के घर पर पत्थर फेंकता है, तो वह सिर्फ गुस्से का दृश्य नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ़ साहस की शुरुआत है। यह बताता है कि सामाजिक बदलाव नागरिकों की जागरूकता से ही संभव है, जो संविधान का मूल संदेश भी है।

फिल्म मंथन सहकारिता आंदोलन के माध्यम से नागरिक भागीदारी का महत्व सिखाती है। यह सीधे-सीधे संविधान की लोकतांत्रिक भावना और लोक-शक्ति की अवधारणा को दर्शाता है।

विभाजन और धर्मनिरपेक्षता की बहस पर आधारित 'गरम हवा' (1973) धार्मिक पहचान के नाम पर होने वाले भेदभाव की मार्मिक दास्तान है। सलीम मिर्ज़ा के परिवार को समाज से अलग-थलग किया जाना यह दिखाता है कि देश में अगर धर्म के आधार पर नफरत फैलेगी, तो संविधान की आत्मा कमजोर होगी।

1990 के दशक में फिल्मों ने मानव गरिमा और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से उठाया। 'दामिनी' (1993) न्याय की धीमी और कठिन प्रक्रिया पर कठोर सवाल उठाती है। अदालत में दामिनी की पुकार 'तारीख़ पर तारीख' आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय का अधिकार तभी सार्थक है, जब वह समय पर मिले। इसी तरह 'थप्पड़' (2020) यह संदेश देती है कि सम्मान और बराबरी प्रत्येक महिला का अधिकार है और किसी भी तरह का अपमान स्वीकार्य नहीं।

नई सदी की फिल्मों में नागरिक जिम्मेदारी का भाव भी मजबूत हुआ। 'रंग दे बसंती' (2006) देकते हुए लगता है कि लोकतंत्र केवल वोट देने का काम नहीं है। अगर व्यवस्था में अन्याय है, तो नागरिकों को सवाल पूछना और बदलाव की मांग करना चाहिए।

आज के समय की महत्वपूर्ण फिल्म Article 15', जिसने संविधान के अनुच्छेद 15 जाति आधारित भेदभाव के विरोध को सीधे कहानी का हिस्सा बनाया। पुलिस अधिकारी का न्याय के लिए संघर्ष हमें याद दिलाता है कि संविधान की रक्षा केवल अदालतों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

आज जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर 'मुल्क', 'पाताल लोक', 'मेड इन हेवन', 'सरदार उधम' जैसी फिल्मों में कहानियाँ यह सवाल पूछती हैं कि क्या हम सच में समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों को अपना पाए हैं?

हाल के वर्षों में बनी फ़िल्में दर्शकों को और गहराई से संवैधानिक मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। 'मुल्क' (2018) धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता के सवाल को बेहद प्रभावशाली ढंग से उठाती है। फिल्म यह दिखाती है कि देशभक्ति किसी धर्म की बपौती नहीं होती और किसी एक व्यक्ति की गलती के आधार पर पूरे समुदाय को आरोपी बनाना संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। अदालत में दिया गया तर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारतीय पहचान धर्म से नहीं, बल्कि संविधान से तय होती है। इसी तरह 'लापता लेडीज़' (2024) महिलाओं की स्वतंत्रता, सुरक्षा और पहचान को हास्य और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। फिल्म यह सवाल उठाती है कि क्या विवाह के बाद महिला की इच्छा और अस्तित्व का महत्व खत्म हो जाता है?

यह दर्शकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संवैधानिक अधिकार के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 'कटहल' (2023) प्रशासन की असली प्राथमिकताओं पर व्यंग्य करती है, जहां जनता की समस्याओं को अनदेखा करके सत्ता कभी-कभी सतही मुद्दों पर समय और संसाधन खर्च करती है। यह फिल्म दर्शकों को समझाती है कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब शासन जनता की वास्तविक ज़रूरतों को प्राथमिकता दे। 'पिंक' (2016) महिला की सहमति और सम्मान को केंद्र में रखती है, और 'नो मतलब नो' जैसे सरल संवाद के माध्यम से संविधान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को बेहद असरदार तरीके से सामने लाती है। वहीं 'थप्पड़' (2020) यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे बड़ा मूल्य है, और हिंसा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो संविधान के समानता और गरिमा के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इन फिल्मों को संवैधानिक दृष्टि से देखने पर दर्शक महसूस करेंगे कि सिनेमा केवल कहानी नहीं दिखाता, बल्कि समाज से यह पूछता है कि क्या हम वास्तव में उन मूल्यों पर जी रहे हैं, जिनकी नींव पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है।

वैधानिक दृष्टि से सिनेमा को देखना दर्शकों को अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। यह दृष्टि उन्हें सिर्फ़ दर्शक से सक्रिय नागरिक में बदल देती है। जब फिल्में समाज में बदलाव की ऊर्जा पैदा करती हैं और दर्शक उस बदलाव का हिस्सा बनते हैं, तभी सिनेमा और संविधान दोनों अपना वास्तविक उद्देश्य पूरा करते हैं। अब समय है कि दर्शक पर्दे पर दिखने वाली कहानी के पीछे छिपे संवैधानिक संदेश को पहचानें और सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाएं।

जीवन को सुखद रूप देने की प्रेरक यात्रा

नया साल

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

नया साल केवल तारीखों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने, आत्मचिंतन करने और सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण अवसर है। जब एक वर्ष समाप्त होता है, तो उसके साथ अनेक अनुभव, सफलताएँ, असफलताएँ और सीख भी हमारे मन में संचित रहती हैं। नया साल हमें यह अवसर देता है कि हम बीते हुए कल से सीख लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाएँ और भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करें। यदि हम सही सोच और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएँ, तो नया साल हमारे जीवन को न केवल सुखद बना सकता है, बल्कि उसे अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण भी बना सकता है।

नए साल की शुरुआत आत्ममंथन से होनी चाहिए। आत्ममंथन का अर्थ है स्वयं के भीतर झाँकना और ईमानदारी से यह मूल्यांकन करना कि हमने बीते वर्ष में क्या सीखा, कहाँ गलतियाँ कीं और किन बातों ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह प्रक्रिया हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी क्षमताओं को समझने में सहायता करती है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी सुधार की वास्तविक शुरुआत होती है। आत्ममंथन के बिना किया गया कोई भी संकल्प खोखला सिद्ध हो सकता है।

आत्ममंथन के बाद आता है संकल्प। संकल्प केवल कहने की बात नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में उतारना ही उसका वास्तविक अर्थ है। नए साल में बड़े और अव्यावहारिक लक्ष्य बनाने के बजाय छोटे, स्पष्ट और यथार्थवादी संकल्प लेना अधिक प्रभावी होता है। जैसे नियमित अध्ययन करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समय का सदुपयोग करना या परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। छोटे-छोटे संकल्प निरंतर अभ्यास से आदत बन जाते हैं और यही आदतें जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। जब संकल्प कर्म में बदलता है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। नए साल का सबसे सुंदर उपहार है सकारात्मक सोच। जीवन में परिस्थितियाँ सभी के लिए समान रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं, पर उनका प्रभाव हमारी सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिन परिस्थितियों में भी अवसर देखने की क्षमता देता है। असफलता को अंत मानने के बजाय यदि हम उसे सीख समझें, तो वही असफलता सफलता की सीढ़ी बन सकती है। सकारात्मक सोच न केवल मानसिक शक्ति बढ़ाती है, बल्कि जीवन को अधिक आनंदमय भी बनाती है।

जीवन का वास्तविक सुख संबंधों की मधुरता में निहित है। नए साल में हमें अपने पारिवारिक, सामाजिक और मित्रता के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा, संवाद और सहयोग से रिश्तों में नई ऊर्जा आती है। पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर प्रेम और समझ के साथ आगे बढ़ना ही नए साल का सच्चा स्वागत है। जब संबंध मजबूत होते हैं, तो जीवन स्वयं ही आनंद से भर उठता है। जीवन को गहराई और उद्देश्य देने के लिए सेवा और संवेदना भी आवश्यक है। केवल अपने लिए जीना जीवन का पूर्ण अर्थ नहीं है। दूसरों की सहायता करना, किसी जरूरतमंद का सहारा बनना या समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना—ये सभी कार्य जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सेवा से आत्मसंतोष प्राप्त होता है और आत्मसंतोष ही स्थायी सुख का आधार है। अंततः, नए साल का स्वागत आशा और विश्वास के साथ होना चाहिए। भविष्य भले ही अनिश्चित हो, पर परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर उसे सुंदर बनाया जा सकता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। यदि हम ईमानदारी और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।झ नया साल जीवन को सुखद और नया रूप देने का एक अनमोल अवसर है। आत्ममंथन, संकल्प, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य, समय प्रबंधन, संबंधों की मधुरता और सेवा ,ये सभी मिलकर जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। जब हम नए साल को केवल उत्सव नहीं, बल्कि परिवर्तन का माध्यम मानते हैं, तभी वह हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश लेकर आता है। यही नए साल का वास्तविक स्वागत है और यही वह प्रेरक यात्रा है, जो जीवन को बेहतर, सुखद और सार्थक बना सकती है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समझदार होना सिर्फ हां कहने जितना आसान है

व्यंग्य

मुकेश नेमा

लेखक मध्यप्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं।

पति के पास उपलब्ध सर और गर्दन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल उसे उस वक्त हाँ में हिलाना है जब पत्नी साड़ी ख़रीदते वक्त किसी साड़ी के बारे में उसकी राय पूछे।किसी भी पति के लिये साड़ियाँ ख़रीदने का मौक़ा अपनी वफ़ादारी साबित करने का सबसे बेहतरीन मौक़ा होता है ।कोई भी समझदार बंदा इसे गँवाता नही।वैसे तो आदमी पति होते ही समझदार हो जाता है।जो समझदार होने में देर करते हैं वो पति रह भी जायेंगे या नही ,कब तक पति रह सकेंगे ये कहना मुहाल है।

और फिर समझदार होना बड़ा आसान भी है। आपको बस हाँ कहना होता है।पत्नी की हाँ में हाँ मिलना होती है।आपको इतना भर भाँपना है कि आपकी पत्नी किस साड़ी को पसंद कर चुकी है।पत्नी आपसे उस साड़ी बाबत आपकी राय जानना चाहती है जिसे व इसे जज होने का मौक़ा समझेगें तो गलती करेंगे।वो उस वक्त आपसे केवल और केवल हाँ की उम्मीद कर रही होती है।

साड़ियाँ आपको यह मौक़ा देती है कि पत्नी आपको कुछ वक्त के लिये ही सही पर खुशमिजाज ,काबिल और होशियार मान ले।कई बार साड़ियाँ आपसे सच में समझदार होने की माँग करती हैं।फ़र्ज़ कीजिये आपकी पत्नी आधा दर्जन साड़ियाँ पसंद कर चुकी और अब चाहती है कि आप उनमे से एक दो पसंद कर दें ।चूँकि आप अब तक बीबी की पसंद की गई साड़ियों के ढेर से दबे थे।सांस नहीं ली जा रही थी आपसे।ऐसे में एक या दो वाला ऑफ़र आपने जान डाल देता है।आप फ़ौरन उस ढेर में से कोई सी भी दो साड़ियाँ चुनते हैं और पत्नी को थमा देते हैं।

आप में यदि थोड़ी बहुत भी अक़्ल होती तो आप उससे सारी साड़ियाँ ले लेने की ज़िद करते।पर अब आप गलती कर चुके।चुनी गई साड़ियों को लेकर घर पहुँचते पहुँचते आपकी पत्नी को छोड़ी गई साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आने लगती है !।चूँकि वो साड़ियाँ ना ख़रीदी जाने की वजह आप है इसलिये डिनर भी आपका ही बिगड़ेगा ये बात भी तय हो जाती है।

अक़्लमंद पति साड़ियों से घिरी बीबी के आसपास बना रहता है।अपने धीरज का दामन मज़बूती से थामे रखता है वो।बीबी उससे साडी देखने परखने की उम्मीद हांलाकि कभी करती नही।पर यदि करती है तो वह पूरी गंभीरता से यह ज़िम्मेदारी निभाता है।साड़ी का एक कोना पकड़कर उसे पूरे गौर से देखता है।टटोलता है और ख़ाक समझ में ना आने के बावजूद लग तो ठीक ही रही है जैसी अस्पष्ट सी राय देता है।साड़ी के बारे में साफ़ साफ़ हाँ या ना कहना ख़तरनाक होता है।ऐसे बड़े मामले निपटाने की कोशिश बाद में मुश्किल का सबब बन सकती है उसके लिए।वह जानता है कि ये मामला पत्नी खुद सुलटाये वही उसके लिये ठीक है।

वैसे पति जैसे जैसा पुराना होता जाता है उसे अकल आने लगती है।पुराना पति पत्नी की ख़रीदी गई साड़ियों पर चस्पाँ रेट के टैग को देखने की गलती नहीं करता।वह सामने मौजूद हर साडी को बढ़िया ,बेहतरीन ,माशाअल्लाह करार देता है।पत्नी के कलर च्वाईस पूछने पर लाल पीले नीले के फेर में ना पड़कर वह अपनी बीबी को हजार बार पहले भी कही जा चुकी बात एक बार फिर बताता है।वह उसे बताता है तुम पर हर कलर जँचता है।और ऐसी हर साडी जो उसे पसंद आ रही है ज़रूर ख़रीद ली जाना चाहिए।

साड़ी ख़रीदना वो खेल है जिसमें पति केवल दर्शक दीर्घा में ही रहता है।समझदार पति इस खेल के मैदान में नहीं कूदते और दूर से अपनी सीट पर बैठे बैठे केवल तालियाँ बजाते है।समझदार हो चुका पति जानता है कि साड़ियाँ ख़रीदना एक कला है जिसमें उसकी पत्नी पारंगत है।ये वो कौशल है जिसमें उसकी पत्नी का हाथ हमेशा से साफ़ है।ये वो लडाई है जिसे उसकी पत्नी ही जीत सकती है।ऐसे में वो साड़ी ख़रीदने जैसे बेहद ख़ास काम से दूरी बनाये रखता है और सुखी बना रहता है।

जब पत्नी साड़ियाँ ख़रीद रही हो।साड़ियों की दुकान पर युग बीत चुके हों।ऐसे वक्त पर घड़ी देखना,मुँह बनाना,सर खुजलाना जैसी हरकतें आपका नुक़सान कर सकती हैं।यदि आप नही चाहते कि आपकी पत्नी आपको बच्चों के सामने ,सिर्री ,अकडू और बोर करार दे दे तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए।पत्नी के साडी ख़रीदो कार्यक्रम के दौरान जो पति अनमना होकर दिखाता है।उबासी लेता है या पाँव पटकता है ,उसे गधा मानने मे मुझे क़तई दिक़्क़त है नही।ऐसे पति अपनी पत्नी से उसी बर्ताव के लायक़ है जैसे एक नाराज़ कुम्हार अपने गधे के साथ करता है।

आप किस क़िस्म के पति है मैं नहीं जानता पर इतना भर कहना है मेरा कि यदि आपने शादीशुदा होने के बावजूद साड़ी ख़रीदने जैसे नाजुक वक्त में अपनी गर्दन और उसके ऊपर मौजूद सर को क़ायदे से हिलाना अब तक नहीं सीखा है तो बिना देर किये अब सीख लें।इसलिये सीख लें ,क्योंकि आपकी गर्दन साड़ियों से ज़्यादा क़ीमती है।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

कागजों पर बची शादी को बनाए रखना अनुचित

सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि लंबे समय तक लंबित वैवाहिक मुकदमे न केवल पक्षकारों के लिए बल्कि समाज के लिए भी किसी लाभ के नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में विवाह संबंध को बनाए रखना केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो केवल कागजों पर अस्तित्व में हो और जो वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी के कारण वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी हो। न्यायालय ने चौबीस वर्षों से अलग रह रहे एक दंपत्ति की शादी को समाप्त करते हुए कहा कि लंबे समय तक अलगाव और एक-दूसरे को स्वीकार न करने की जिद, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के समान है। यह विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का स्पष्ट उदाहरण है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने पति की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलाक के आदेश को बहाल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा कि लंबे समय तक लंबित वैवाहिक मुकदमे न केवल पक्षकारों के लिए बल्कि समाज के लिए भी किसी लाभ के नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में विवाह संबंध को बनाए रखना केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस मामले में पति और पत्नी का विवाह वर्ष 2000 में हुआ। वे महज एक वर्ष के भीतर ही दोनों अलग भी हो गए। इसके बाद दोनों पिछले लगभग 24 वर्षों से अलग रह रहे थे। इस विवाह से कोई संतान भी नहीं थी। पति ने पहली बार सन् 2003 में तलाक की याचिका दायर की थी। इसे समय से पहले मानते हुए खारिज कर दिया गया। इसके बाद सन् 2007 में दायर दूसरी याचिका को विचारण न्यायालय ने परित्याग के आधार पर स्वीकार कर ली। हालांकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सन् 2011 में इस फैसले को पलटते हुए कहा कि पत्नी के पास वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण था और पति अपने ही दोष का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। इस फैसले के खिलाफ पति ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब दंपति इतने लंबे समय से अलग रह रहे हों तब यह तय करना अप्रासंगिक हो जाता है कि गलती किसकी थी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक अलगाव स्वयं में दोनों पक्षों के लिए क्रूरता है। ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का उपयोग करते हुए विवाह को समाप्त किया जा सकता है। निर्णय में कहा गया कि दोनों पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन को लेकर दृष्टिकोण पूरी तरह अलग थे। उन्होंने लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने से इंकार भी किया। यह व्यवहार ही परस्पर क्रूरता के दायरे में आता है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि वैवाहिक मामलों में न तो समाज और न ही न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है कि किसका दृष्टिकोण सही है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ रह पाने में असमर्थ हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में राकेश रमन बनाम कविता (2023) सहित कई पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक बिना किसी सुलह की संभावना के अलग रहना दोनों पक्षों के प्रति क्रूरता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही संविधान पीठ के निर्णय शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति वैधानिक तलाक कानूनों में निहित दोष सिद्धांत से बाधित नहीं होती। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कुमारी रेखा बनाम शंभू सरन पासवान (2025) के फैसले का भी संदर्भ दिया। इसमें कहा गया था कि यदि विवाह का अपूरणीय विघटन हो चुका हो, तो वैधानिक आधारों की अनुपलब्धता भी सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत हस्तक्षेप करने से नहीं रोकती। यह पहली बार नहीं है जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है। इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय ने अपने सन 2023 में दिए एक फैसले में यही बात कही थी।

न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (अधिनियम) की धारा 13 की विवेचना भी की। यह धारा तलाक के लिए विभिन्न आधार प्रदान करता है। न्यायालय ने विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भी चर्चा की। इसके द्वारा 1976 का संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया था और अधिनियम में खंड (पं) और (पइ) को धारा 13 और धारा 13 । में जोड़ा गया था। न्यायालय ने उल्लेख किया कि विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 के उद्देश्य और कारणों में तलाक से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाए अधिनियम के तहत कार्यवाही के त्वरित निपटान को सक्षम करना और कुछ विसंगतियों और बाधाओं को दूर करना जो अधिनियमों के पारित होने के बाद सामने आए हैं, शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि संसद का इरादा तलाक के प्रावधान को उदार बनाने के लिए बहुत स्पष्ट था। साथ ही अलग हो चुकी पत्नी के लिए आवश्यक सुरक्षा के प्रति सचेत भी था।

अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत ''क्रूरता'' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसलिए, न्यायालय को इसे उदारता से और प्रासंगिक रूप से लागू करने के लिए बहुत व्यापक विवेकाधिकार देता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकती है। इसलिए, तलाक देने की याचिका का विरोध करने वाले पतिध्पत्नी की स्थिति की उचित समझ होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, शैक्षिक योग्यता, वित्तीय स्थिति, रोजगार, जाति, समुदाय, आयु और स्थान जैसे कारकों के आधार पर परिणाम और प्रभाव व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। न्यायालय ने विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल का भी उल्लेख किया। इसमें यह कहा गया था कि ''क्रूरता'' अभिव्यक्ति का मानव आचरण या मानव व्यवहार के साथ एक अविभाज्य संबंध है। यह हमेशा उस सामाजिक स्तर या परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें विभिन्न पक्ष शामिल होते हैं। उनके जीवन के तरीके, संबंध, स्वभाव और भावनाएं जो उनकी सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होती हैं।

न्यायालय ने कहा कि किसी मामले में एक महिला के लिए क्रूरता एक पुरुष के लिए क्रूरता नहीं हो सकती है। इसलिए, जब हम एक ऐसे मामले की जांच करते हैं जिसमें एक पत्नी तलाक चाहती है तो अपेक्षाकृत अधिक लोचदार और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, तलाक का कानून मुख्य रूप से गलती सिद्धांत के आधार पर एक रूढ़िवादी कैनवास पर बनाया गया था। हालांकि, एक उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाने के साथ, अलग होने या विवाह के विघटन के आधार को अक्षांशवाद के साथ समझा गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वैवाहिक कानूनों के इस तरह के उदार निर्माण के साथ भी, सामाजिक-आर्थिक कलंक और तलाक या अलगाव के कारण एक महिला से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं।

न्यायालय ने तलाक के प्रावधानों को लागू करते समय 'सामाजिक-संदर्भ सोच' को अपनाने, सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ-साथ न्यायालयों द्वारा पक्षों की स्थिति और पृष्ठभूमि को अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने तलाक के लिए एक याचिका में बोझ के सवाल पर चर्चा की और कहा कि सबूत का बोझ याचिकाकर्ता पर है। हालांकि, संभावना की डिग्री उचित संदेह से परे नहीं है, बल्कि प्रधानता की है। न्यायालय ने धारा 23 (1) का अवलोकन किया जो कार्यवाही में डिक्री का प्रावधान करती है और कहा कि यह राहत पाने के लिए कानून के दुरुपयोग और दुरुपयोग के मामलों की जांच करने के लिए सावधानी का एक शब्द है। न्यायालय ने कहा कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक घर, जो रहने के लिए एक खुशहाल और प्रिय स्थान है, दुख और पीड़ा का स्रोत बन जाता है जहां साथी लड़ते हैं और बच्चे उक्त झगड़ों के सीधे शिकार हो जाते हैं। विवाह के टूटने में व्यावहारिक रूप से उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है। उन्हें अपूरणीय क्षति होती है।

विशेष रूप से जब दंपति आपस में झगड़ते हैं, बेपरवाह रहते हैं और उस पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव के बारे में बेपरवाह रहते हैं। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 23 (2) की भी विवेचना की। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय अधिनियम के तहत कोई राहत देने से पहले, पहली बार में, जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में संभव हो, पक्षों के बीच सुलह लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। न्यायालय ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य और उद्देश्य दोनों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का लाभ उठाते हुए किसी भी पक्ष की जांच करना है। इस तथ्य को देखते हुए कि कई अवसरों पर तलाक एक समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन दूसरा तब पैदा होता है जब महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग हो जाती है।

वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष डेढ़ दशक से अलग रह रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि शादी अब मौजूद नहीं है। रिश्ते को तलाक की औपचारिक डिक्री के अलावा अन्यथा समाप्त कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि पति द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोप उतने ही गंभीर हैं जितने कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ लगाए गए आरोप। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष दूर चले गए थे और अपने-अपने जीवन में ब गए थे। इसलिए उनके साथ रहने के बिना केवल स्थिति की पीड़ा को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री को अस्वीकार करने में एक अति-तकनीकी और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। इसलिए, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री को मंजूरी दे दी।

मजहब और सियासत- अपनों के खिलाफ जंग

विचार

सपना सी.पी. साहू 'स्वप्निल'

अशांति और हिंसा का समाधान केवल शांति, आपसी संवाद और कट्टरपंथ के विरोध से ही संभव है। यह एक गंभीर और विचारणीय विषय है। वैश्विक स्तर पर हो रही इन घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिस मजहब का मूल अर्थ अमन, शांति है, उसी के नाम पर हो रही हिंसा ने आज पूरी मानवता को संकट में डाल दिया है। यह कट्टरपंथ अब केवल अन्य धर्मों के विरोध तक सीमित न रहकर एक व्यापक वैश्विक संकट बन चुका है। वैसे तो इतिहास के पन्नों में शिया-सुन्नी संघर्ष पुराने रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर विश्वास ही अपनों के विरुद्ध शस्त्र बन रहा है। हाल ही में हमने विश्व अल्पसंख्यक दिवस के दिन ही देखा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की। उसे मजहबी नारों के साथ ईश निंदा का दोष सिद्ध हुए बिना ही मारकर, जिंदा जला दिया।

वैश्विक स्तर पर सीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों में हो रही हिंसा और कट्टरपंथी संघर्ष अत्यंत चिंताजनक हैं। जब धार्मिक कट्टरता मानवता पर हावी होती है, तो निर्दोष लोग ही इसका शिकार बनते हैं। भारत के संदर्भ में, हमारी सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव पर टिकी है। भारतीय समाज की शक्ति उसकी विविधता और आपसी तालमेल में है। बाहरी देशों के हिंसक संघर्षों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना जटिल है, क्योंकि भारत का सामाजिक ताना-बाना और लोकतांत्रिक ढांचा इसे एक विशिष्ट पहचान देता है।

अशांति और हिंसा का समाधान केवल शांति, आपसी संवाद और कट्टरपंथ के विरोध से ही संभव है। यह एक गंभीर और विचारणीय विषय है। वैश्विक स्तर पर हो रही इन घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिस मजहब का मूल अर्थ अमन, शांति है, उसी के नाम पर हो रही हिंसा ने आज पूरी मानवता को संकट में डाल दिया है।

यह कट्टरपंथ अब केवल अन्य धर्मों के विरोध तक सीमित न रहकर एक व्यापक वैश्विक संकट बन चुका है। वैसे तो इतिहास के पन्नों में शिया-सुन्नी संघर्ष पुराने रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर विश्वास ही अपनों के विरुद्ध शस्त्र बन रहा है। हाल ही में हमने विश्व अल्पसंख्यक दिवस के दिन ही देखा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की। उसे मजहबी नारों के साथ ईश निंदा का दोष सिद्ध हुए बिना ही मारकर, जिंदा जला दिया। यह दुखित और द्रवित करने की घटना से यह तो समझा जा सकता है कि वहां एक अल्पसंख्यक व्यक्ति निशाना बना जो उस मजहब में आस्था नहीं रखता था, किंतु इसके बाद सीरिया, इराक, नाइजीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाली खबरें कहीं अधिक विचलित करने वाली हैं। विडंबना यह है कि इन संघर्षों में शिकार होने वाले और हमला करने वाले, दोनों अक्सर एक ही ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। यह अल्लाह के बंदों का अल्लाह के बंदों के खिलाफ युद्ध समाज के लिए एक गहरा घाव बन चुका है। यह आतंकवाद का कैसा रूप है, जो संवेदनाओं से परे है।

इन संघर्षों के मूल में वैचारिक और सांप्रदायिक मतभेद गहरे हैं। सीरिया और यमन जैसे देशों में हिंसा का एक बड़ा कारण राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को मजहबी रंग देना है। अब तो कट्टरपंथी गुट निर्दोष नमाजियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। जब प्रार्थना स्थलों (मस्जिदों) में धमाके होते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमलावरों के लिए मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है।

देखने में आया है कि कट्टरपंथ और आतंक का विस्तार निरंतर हो रहा है। नाइजीरिया में बोको हरम और मध्य-पूर्व में आईएसआईएस जैसे संगठनों ने मजहब की अतिवादी व्याख्या की है। ये संगठन उन लोगों को भी अपना दुश्मन मानते हैं जो उनकी संकीर्ण विचारधारा से सहमत नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, सबसे अधिक मानवीय क्षति स्वयं मुस्लिम समुदायों को उठानी पड़ी है। इन घटनाओं के पीछे अक्सर स्थानीय सत्ता की लालसा और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का हस्तक्षेप भी दिखाई देता है। हथियारों की होड़ और संसाधनों पर कब्जे की राजनीति ने इन क्षेत्रों को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है, जहां आम नागरिक केवल एक 'संख्या' बनकर रह गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक वैश्विक सीख है कि हम सनातनियों ने सदियों से विभिन्न मतों और पंथों को साथ लेकर चलने की कला सीखी है। जहां दुनिया के कई हिस्से संकीर्णता के कारण जल रहे हैं, भारत की सहिष्णुता और लोकतंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह है। कट्टरपंथ चाहे किसी भी पक्ष का हो, वह अंततः विनाश ही लाता है।

अंततः, जब किसी भी धर्म का मार्ग करुणा के बजाय नफरत की ओर मुड़ जाता है, तो वह धर्म नहीं रह जाता। दुनिया को आज घातक हथियारों की नहीं, बल्कि उस रूहानी शांति की जरूरत है जो इंसान को इंसान से जोड़ सके। आज आतंकवाद केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की साझी चुनौती बन चुका है। इबादत के तरीके अलग हों तो क्या, लहू का रंग तो सबका एक ही है, अगर इंसान ही न बचा इस जहां में, तो फिर मज़हब और खुदा कौन है?

परंपरा पर भारी महंगाई

मनोज जानी

लेखक पत्रकार हैं।

चांदी की चमक से फीकी हुई आदिवासियों की मुस्कान

आदिवासी क्षेत्रो में आज एक ही चर्चा है, 'चांदी घणी महंगी वेई गई, अब छोरी री शादी केम करंगा?' (चांदी बहुत महंगी हो गई, अब बेटी की शादी कैसे करेंगे?)। यह केवल एक सवाल नहीं, बल्कि उन हजारों पिताओं की सिसकी है जो रात भर जागकर अपनी जमीन बचाने की जुगत लगाते हैं।आदिवासी समाज में चांदी केवल जेवर नहीं है, वह 'हाख' (साख) है। जब तक हाथ में भारी कड़ा और गले में चांदी की हसली न हो, तब तक आदिवासी का श्रृंगार और उसका सामाजिक सम्मान अधूरा माना जाता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि-खेत बिकाऊ हैं, पर रीति निभानी है- एक तरफ मजदूरी 300-400 रुपये से आगे नहीं बढ़ रही, और दूसरी तरफ चांदी 2 लाख के करीब पहुँच रही है। मक्का बेचकर चांदी लाना अब मुमकिन नहीं रहा। साहूकारों का 'सोना' गरीब की मजबूरी ही साहूकार की चांदी बन गई है।

भारत का आदिवासी समाज, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और सादगी के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। यह संकट किसी अकाल या प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि चांदी के बढ़ते दामों और बाजारवाद की उस बेरुखी से पैदा हुआ है जिसने गरीब आदिवासी वर्ग को अपनी ही परंपराओं से दूर होने पर मजबूर कर दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में चांदी महज एक धातु नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व, मान-सम्मान और सामाजिक ताने-बाने का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन जिस रफ्तार से चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, उसने आदिवासी समाज की कमर तोड़ दी है।

चांदी की राजनीति और मरती परंपराएं- क्या आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है ?- जब दिल्ली के गलियारों में अर्थव्यवस्था के 'पांच ट्रिलियन' होने के दावे किए जाते हैं, तब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के आदिवासी अंचलों में एक बाप अपनी जमीन का पट्टा साहूकार के पास गिरवी रख रहा होता है। क्यों ? क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी में 'चांदी' देनी है। यह चांदी उसके लिए निवेश नहीं, बल्कि उसकी नाक का सवाल है। लेकिन सरकार की नीतियां इस 'सांस्कृतिक विवशता' को समझने में पूरी तरह अंधी साबित हुई हैं।

गौरतलब है कि आदिवासी समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक और विवाह से लेकर 'मोण' (मृत्यु भोज या स्मारक समारोह) तक, चांदी के लेन-देन की गहरी जड़ें हैं। हसली, कड़ा, बाजूबंद और पायजेब जैसे आभूषण केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का मानक हैं। शादी-ब्याह में बेटी को चांदी देना या रिश्तेदारों में चांदी के सिक्कों का लेन-देन एक ऐसी अनिवार्यता है।

शेयर बाजार और निवेशकों के लिए चांदी 'सेफ हेवन' (सुरक्षित निवेश) हो गया है लेकिन आदिवासी के लिए समस्या। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता आती है तो निवेशक चांदी बटोरने लगते हैं जिससे दाम बढ़ते हैं। इस सट्टेबाजी और वैश्विक उठापटक का सीधा प्रहार उस गरीब पिता पर पड़ता है जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक किलो चांदी जुटानी है।

जब परंपरा निभानी अनिवार्य हो और जेब खाली हो, तो केवल एक ही रास्ता बचता है- कर्ज। आज आदिवासी क्षेत्रों में सूदखोरों और साहूकारों का धंधा फिर से फल-फूल रहा है। चांदी खरीदने के लिए आदिवासी अपनी जमीन गिरवी रख रहा है या भारी ब्याज दर पर उधार ले रहा है। यह कर्ज चुकाने के लिए युवा शहरों व अन्य राज्यो की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां वे निर्माण स्थलों पर हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं। चांदी की चमक के पीछे पसीने की वह गंध है, जिसे नीतियां बनाने वाले कभी नहीं समझ पाते। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक त्रासदी है। सरकार की अनदेखी और खोखले दावेभारत सरकार ÷जनजातीय गौरव दिवस÷ मनाती है और आदिवासी कल्याण के बड़े-बड़े विज्ञापन देती है। लेकिन क्या कभी किसी मंत्रालय ने इस बात का अध्ययन किया कि बढ़ती महंगाई ने आदिवासी रीति-रिवाजों को कैसे प्रभावित किया है ?

प्रमुख कारण- जीएसटी की मार-विलासिता की वस्तुओं और अनिवार्य सांस्कृतिक वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया। चांदी पर लगने वाला टैक्स एक गरीब आदिवासी के लिए अतिरिक्त बोझ है। बाजार नियंत्रण का अभाव-सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आदिवासी सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें रियायती दरों पर या उचित मूल्य पर चांदी उपलब्ध करा सके, ताकि उनकी परंपराएं सुरक्षित रहें। आय और खर्च का असंतुलन-सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने में कंजूसी करती है, लेकिन बाजार की बेलगाम कीमतों को रोकने में पूरी तरह विफल रही है।

चांदी के बढ़ते भाव आदिवासी समाज के लिए केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनकी खुशियों पर लगा 'ग्रहण' है। सरकार को समझना होगा कि यदि एक वर्ग अपनी परंपराओं को निभाने के लिए कर्ज के दलदल में धंसता चला गया, तो वह समाज कभी मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाएगा।सोने-चांदी की चमक महलों तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन इसकी आंच अगर किसी गरीब की झोपड़ी और उसकी बेटी की शादी को जलाने लगे, तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। अब समय आ गया है कि सरकार इस 'सफेद धातु' के पीछे छिपे 'काले सच' को देखे और आदिवासी समाज को इस आर्थिक घुटन से राहत दिलाए।

एक तरफ सरकार डिजिटल लेनदेन और पारदर्शिता की बात करती है, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में 'चांदी का संकट' साहूकारों के लिए चांदी काटने का जरिया बन गया है। चांदी के भाव 2,00,000 प्रति किलो की ओर बढ़ रहे हैं, और गरीब आदिवासी के पास न तो बैंक से लोन लेने की सुविधा है और न ही इतनी बचत। नतीजा यह है कि वह साहूकार से 5 प्रति से 10 प्रति मासिक ब्याज पर पैसा उठाता है। यह ब्याज की दर नहीं, बल्कि एक जीते-जाते इंसान की कब्र खोदने की तैयारी है।

क्या है समाधान- रियायती चांदी काउंटर-जिस तरह राशन की दुकानों पर अनाज मिलता है, सरकार को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष 'सांस्कृतिक कोटा' के तहत सीमित मात्रा में रियायती दरों पर चांदी उपलब्ध कराने की योजना बनानी चाहिए। टैक्स में छूट-जनजातीय क्षेत्रों के लिए चांदी के पारंपरिक आभूषणों पर जीएसटी में विशेष रियायत दी जानी चाहिए। आय में वृद्धि-जब तक आदिवासी ओर खेती किसानी वाले तबके की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, वह महंगाई से नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए उपज के दामों में भारी बढ़ोतरी अनिवार्य है।

जागरूकता अभियान-समाज सुधारकों और सरकार को मिलकर आदिवासी समाज को अत्यधिक गहनों के प्रदर्शन के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन यह तब होगा जब उन्हें विकल्प दिया जाए।

ऐतिहासिक भोजशाला में परंपरा अनुसार पांच दिवसीय भोज महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा

धार। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला व मां वाग्देवी की मुक्ति एवं उसके गौरव की पुर्नस्थापना हेतु हिंदू समाज द्वारा प्रति मंगलवार सत्याग्रह किया जा रहा है ।ऐतिहासिक भोजशाला में पांच दिवसीय भोज महोत्सव कार्यक्रम 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे। समिति द्वारा नगर में संवाद केंद्र (कार्यालय) का शुभारंभ किया गया ।

मां वाग्देवी के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1008 श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज श्रृंगेश्वर धाम जूना अखाड़ा राष्ट्रीय सचिव के करकमलों द्वारा संवाद केंद्र (कार्यालय) का शुभारंभ किया गया ।

1008 श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज द्वारा प्रेस वार्ता में सबसे आह्वान किया की मां सरस्वती की मुक्ति एवं उसके गौरव की पुर्नस्थापना हेतु हम सतत प्रयत्नशील हैं लगातार 502 वर्षों के संघर्ष और लाखों हिंदू जनों के बलिदान के पश्चात आज सकल हिंदू जनों के सहयोग से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है हम सभी के प्रयासों से भोजशाला का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है सर्वे रिपोर्ट पर भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आना शेष है अगर हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तो भोजशाला में मां वाग्देवी विराजित होगी ।

हमारी भोजशाला के दरवाजे भी हिंदुओं के संघर्ष एवं बलिदानों से खुले हैं भोजशाला की पूर्ण मुक्ति एवं उसके गौरव की पूर्ण स्थापना भी हम हिंदूजनों के लगातार प्रयत्नों से ही होगी । इसमें आपकी सहभागिता एवं सक्रियता आवश्यक है आप सभी हिंदूजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को अखंड पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो।

संवाद केंद्र कार्यालय के शुभारंभ के पहले संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ गोपाल शर्मा ने अतिथि 1008 श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज श्रृंगेश्वर धाम जूना अखाड़ा राष्ट्रीय सचिव को भोजशाला के दर्शन कर भोज शाला के इतिहास एवं संघर्ष के बारे में अवगत कराया।

संवाद केंद्र कार्यालय एवं प्रेस वार्ता का संचालन निखिल जोशी ने किया । भूमिका एवं अतिथि परिचय महामंत्री सुमित चौधरी ने दिया ।अतिथि स्वागत अध्यक्ष सुरेश चंद्र जलोदिया ने किया । कार्यक्रम की घोषणा महाप्रबंधक हेमंत दोराया ने की। कार्यक्रम में समिति सदस्य भी उपस्थित थे। जानकारी मीडिया प्रभारी मोहन राठौर ने दी।

श्री राजेंद्र सूरी शास. महा. सरदारपुर राजगढ़ की टीम ने कालेज चलो अभियान चलाया

धार। श्री राजेंद्र सूरी शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर राजगढ़ की कालेज चलो अभियान की टीम प्रो. सरिता जैन के मार्गदर्शन में श्री एटम इंटरनेशनल स्कूल राजगढ़ पहुंची । प्रिंसिपल अमन भंडारी एवं दामोदर ने टीम का स्वागत किया । उपस्थित विद्यार्थियों को टीम ने कॉलेज चलो अभियान के बारे में उच्च शिक्षा की ओर से जारी निर्देशों से परिचय करवाया । प्रो. लालिमा विजयवर्गीय ने महाविद्यालय में सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ,आवास योजना, आदि के बारे में जानकारी दी तथा प्रो. ममता लता चौहान ने गांव की बेटी योजना , मेधावी योजना एवं विज्ञान संकाय से संबंधित जानकारी दी प्रो. सरिता जैन ने गांव की बेटी, महाविद्यालय के पुस्तकालय, परीक्षा संबंधी एवं अन्य जानकारी दी ।

टीम श्री राजेन्द्र विद्या संस्कार धाम, मोहनखेड़ा पहुची जहां प्रिंसिपल बुरहानुद्दीन ने विद्यार्थियों का कालेज चलो अभियान टीम से परिचय कराया। टीम के सदस्यों ने विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी । तत्पश्चात् टीम श्री राजेन्द्र विद्या हा.से. स्कूल श्री मोहनखेडा तीर्थ पहुंची वहां प्रिंसिपल नीरव भट्ट ने सभी का बच्चों से परिचय कराया तथा टीम ने उन्हें भी महाविद्यालय से जानकारियां दी। टीम के सभी सदस्यों ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।

सतपुड़ा वैली स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव रन राइज एंड रीजॉइस का रंगारंग समापन

बैतूल। प्रतिष्ठित स्कूल सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस रन राइज एंड रीजाइस का आयोजन बड़े ही उत्साह और जोश के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि निलय डागा, दीपाली निलय डागा एवं स्कूल प्राचार्या डॉ. रीतु बाजपाई ने दीप प्रज्वलन कर की। मुख्य अतिथि निलय डागा ने अपने उद्बोधन में कहा, छात्र-छात्राओं का उज्ज्वल भविष्य इस शिक्षा का आधार है। किताबी ज्ञान के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा छात्रों के जीवन में एक अहम स्थान रखती है। शारीरिक शिक्षा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही हमारे मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें अनुशासन, टीमवर्क और नेतृत्व की क्षमता सिखाती है। आज के इस प्रतिस्पर्धा भरे युग में, शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि वे खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। किताबी ज्ञान और शारीरिक शिक्षा का संगम ही हमें जीवन में सफलता की ऊचाइयों तक पहुचाता है। संबोधन में कहा, खेल हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे टीमवर्क, अनुशासन और परिश्रम की सीख देते हैं। मुख्य अतिथि ने अंडर 19 क्रिकेट में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र तनिस सिंग सोलंकी एवं स्कूल के छात्र जिन्होंने विभिन्न खेलों में राज्यस्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व किया उन्हें सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि एवं निर्देशिका दीपाली डागा का प्रेरणादायक संदेश ने बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कहा, जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, खेल भावना से खेलना महत्वपूर्ण है। दीपाली डागा जी ने कहा,शिक्षा और संस्कार का महत्त्व खेलों से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। खेल हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे टीमवर्क, अनुशासन और परिश्रम की सीख देते हैं। इस तरह के आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों और बच्चों को शुभकामनाएं देती हूं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित- इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी आकर्षक प्रस्तुतियां हुईं। कैम्ब्रिज विंग के छात्रों ने हूला हूप के साथ साड़ी ड्रिल, फ्लैग ड्रिल और योग की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं ईवाई विंग के छात्रों द्वारा फ्लॉवर ड्रिल प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में एक साथ 300 बच्चों ने विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों का प्रदर्शन किया, जबकि 500 छात्रों की सामूहिक प्रस्तुतियों ने सतपुड़ा वैली के खेल मैदान को रंगीन कर दिया। इन शानदार प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अभिभावकों की भी बड़ी भागीदारी रही, उनके लिए भी विभिन खेलो का आयोजन किया गया सभी पालकगणो ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मंच संचालन स्कूल के ईवाय के छात्रों से लेकर आठवीं के छात्रों ने प्रभावी रूप से किया। सतपुडा परिवार ने सभी पालकों का आभार माना।

कुशाभाऊ ठाकरेजी का जीवन राष्ट्रसेवा, अनुशासन और विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है : केंद्रीय राज्यमंत्री ठाकुर

भाजपा के संस्थापक सदस्य कुशाभाऊ ठाकरेजी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया

धार। भाजपा के पितृ पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य कुशल संगठक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर 28 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा जिला कार्यालय धार में केंद्रीय राज्यमंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा ,भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने ,जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष विशाल निगम ने पितृ पुरुष के चित्र पर श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

सावित्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में दोनों महान विभूतियों ने अपने त्याग, तपस्या और संगठन कौशल से भारतीय जनता पार्टी को सशक्त आधार प्रदान किया है। उनका जीवन राष्ट्रसेवा, अनुशासन और विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। नैतिकता, आदर्श व सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ, निष्काम कर्मयोगी श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ने असंख्य युवाओं को देशभक्ति के संस्कार दिए। उनका अभूतपूर्व सांगठनिक कौशल, राष्ट्र चिंतन और अनुशासित जीवन जनसेवा के लिए मार्गदर्शन देता रहेगा।

इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी ,युवा मोर्चा जिला मंत्री जसप्रीत डंग, नवदीप सिंह चौहान, मंडल महामंत्री अमित शर्मा, अल्पना जोशी, प्रतिभा शर्मा, बादल मालवीय, सोनिया राठौर, महेश बोडाने ,पारस चौहान, रजत प्रजापत ,अजय राठौर, जीवन यादव, विशाल माली कुंदन भूरिया, जतिन मौर्य ,नवीन भंवर, श्याम बाबा ,हरीश आर्य ,लखन शर्मा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

तिरुपति विज्ञान सम्मेलन में बैतूल की भरेवा शिल्प को मिला राष्ट्रीय मंच

बैतूल। जिले के लिए यह गौरव का विषय है कि आंध्रप्रदेश के तिरुपति में 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन में बैतूल का पारंपरिक भरेवा शिल्प राष्ट्रीय मंच पर छाया रहा। सम्मेलन का विषय समग्र विकास की भारतीय अवधारणा था। इसमें मध्यप्रदेश से 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया, लेकिन भरेवा शिल्प को बैतूल के शिल्पकार गन्नू रावत ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर विशेष पहचान दिलाई। इस दौरान उनके साथ पत्नी सविता रावत और बेटी देविका रावत भी मौजूद रहीं। सम्मेलन की कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मार्गदर्शन दिया।

पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाईयां न लेने का आव्हान किया

मन की बात जिले की तीन विधानसभाओं, 18 भाजपा मंडलो के 821 बूथों पर सुनी

धार। शासकीय अनुसूचित जाति-जनजाति बालिका छात्रावास धार में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात के 129 वे संस्करण को केंद्रीय राज्यमंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा ,विशाल निगम ने जनजाति लाडली बेटियों के साथ सामूहिक श्रवण किया।

मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2025 में अंतरिक्ष यात्री श्री सुभांशु शुक्ला की सफल वापसी, भारत द्वारा सिन्दूर ऑपरेशन, पुरूष और महिला क्रिकेट टीम द्वारा खिताबी जीत तथा दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम का चैम्पियन बनना प्रमुख घटनाएं रही। मोदी ने आगे कहा कि अगले वर्ष 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनायेंगा। हम अपनी विरासत को नहीं भूले। उन्होंने आगे कहा कि देश के नागरिक बिना चिकित्सकीय सलाह के एन्टिबॉयोटिक दवाईयों का सेवन नहीं करें।

श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी विचारों ने बेटियों में आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने शिक्षा, संस्कार, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देकर बालिकाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। मन की बात का श्रवण कर बालिकाओं में उत्साह, जिज्ञासा और सकारात्मक सोच स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को जिले की तीन विधानसभा18 भाजपा मंडलो में 821 बूथों सहित नगर के सभी बूथों समेत भाजपा जिला कार्यालय पर भी सुना गया इस अवसर पर जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने ,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी, जिला उपाध्यक्ष राखी राय ,अल्पना जोशी सहित भाजपा मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

योजना अधिकारी सुबोध शर्मा 31 दिसंबर को होंगे सेवानिवृत्त 34 साल का समर्पित सेवाकाल हमेशा याद रहेगा

बैतूल। सांसद हो या विधायक या प्रशासनिक अधिकारी, सबके जुबान पर एक शख्सियत का नाम हमेशा रहता है, वह व्यक्तित्व है सुबोध शर्मा। इन सब के द्वारा उनको महत्व देने का मुख्य कारण है उनका सरल व्यवहार व सौंपे गए कार्यों तथा निर्देशों का त्वरित पालन कर बेहतरीन तरीके से कार्य संपादित करना। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में योजना अधिकारी पद पर कार्यरत कार्य के प्रति बेहद समर्पित सुबोध शर्मा 34 वर्ष की अपनी सरकारी सेवाओं को 31 दिसंबर को विराम दे रहे हैं। पुलिस विभाग में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रहे स्व. रामबहादुर शर्मा एवं कुमुद शर्मा के सुपुत्र सुबोध ने अपनी प्राथमिक से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्वालियर संभाग से पूरी की। इस दौरान माध्यमिक स्कूल की एवं स्नातकोत्तर उपाधि शास जेएच कॉलेज से प्राप्त की। 11 नवंबर 1992 को शास उमा. विद्यालय बोरगांव, बैतूल से व्याख्याता के पद से सरकारी सेवा की शुरुआत के बाद अगस्त 1994 में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक (औपचारिकेत्तर शिक्षा) के पद से प्रशासनिक क्षेत्र में कदम रखा, इसके बाद प्रशासक एम.आई.एस., बीईओ, सहायक संचालक, डीपीसी, जिला परीक्षा प्रभारी, मीडिया प्रभारी जैसे जिम्मेदार पद को सफलतापूर्वक संभालते शिक्षा विभाग में योजना अधिकारी के महत्वपूर्ण पद से अब सेवानिवृत हो रहे हैं।

हमेशा नवाचार करने का रहा शौक- श्री शर्मा ने बताया कि उन्हे नवाचार करते रहने की ललक बनी रही। जिले में शिक्षा विभाग में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत कार्य को उन्होने अपने मार्गदर्शन में शुरू करवाकर प्रोत्साहित किया। उनका आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के प्रति भी विशेष रुझान है। वे हमेशा टेबल के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को समझने के लिए प्रयत्नशील रहे। वंचित समूह के आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ उपलब्धता का प्रयास किया। शिक्षा विभाग में जिले की अलग पहचान स्थापित करने हेतु सदैव सक्रिय रहे। जिसके चलते शिक्षा क्षेत्र में राज्य स्तर पर जिले को अग्रिम पंक्ति में रख पाने में सफल रहे। अपने सेवाकाल के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सदैव तत्पर रहे।

वरिष्ठों-कनिष्ठों से ऊर्जा मिली

श्री शर्मा बताते है कि उनके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों से हमेशा स्नेह मिला। इस आत्मीय सहयोग के कारण ही वे पूरी ऊर्जा के साथ काम को अच्छी तरह से संपादित कर पाने में सफल रहे, परिवार से मिले संस्कारों के कारण ही ईमानदारी के शिखर तक पहुंचे। मीडिया साथियों के स्नेह व सहयोग से सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में सफल रहे। उन्होंने बताया सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उनका शिक्षा विभाग के प्रति सहयोग का कर्तव्य हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होने अपने सभी वरिष्ठजनों से मिलने वाले मार्गदर्शन एवं कनिष्ठों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा बताया कि सेवाकाल के दौरान घर परिवार के प्रति जो दायित्वों के निर्वहन में कमी रह गई थी अब उसकी पूर्ति कर पाने को वे प्राथमिकता देंगे।

धार के युवा अधिवक्ता अंशुल राजपुरोहित उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त

धार। मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विधाय कार्य विभाग तथा महा अधिवक्ता कार्यालय जबलपुर द्वारा धार के अभिभाषक अंशुल राजपुरोहित को मध्य प्रदेश शासन की ओर से उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया है धार के इतिहास में पहली बार किसी अधिवक्ता को मध्य प्रदेश शासन द्वारा उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया है ।

अंशुल राजपुरोहित पहले भी धार एवं इंदौर हाई कोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी कर चुके हैं इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्ति की गई है । नियुक्ति पर अधिवक्ताओं एवं मित्रों द्वारा बधाई दी गई।

प्रत्येक हिंदू परिवार तक घर-घर पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए

खेड़ापति हनुमान मंदिर में कलश वितरण एवं रुद्र पूजन हुआ

धार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 4 जनवरी को धार शहर की 14 बस्तियों में व्यापक स्तर पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों और जन-जागरण के उद्देश्य से शनिवार को खेड़ापति हनुमान मंदिर में कलश वितरण एवं रुद्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह अरविंद चौधरी ने कहा कि सभी को ज्ञात है कि हिंदू सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं और प्रत्येक बस्ती में सम्मेलन होना है। ऐसे में आयोजन को किस प्रकार बेहतर बनाया जाए, इस पर हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य सभी हिंदू बंधुओं को जोड़ना है। कोई भी व्यक्ति या वर्ग छूटे नहीं है। यदि यह संकल्प हम सभी का है, तो यही हिंदू सम्मेलन की सच्ची सफलता होगी।

पीले चावल देकर सम्मेलन का निमंत्रण दें, रुद्राक्ष भी वितरित किए जाएं- श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक हिंदू परिवार तक घर-घर पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सभी से आग्रह किया गया कि पीले चावल देकर सम्मेलन का निमंत्रण दें, साथ ही रुद्राक्ष वितरित किए जाएं और प्रत्येक घर पर भगवा झंडी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज की सहभागिता से समाज के लिए होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में हमें विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग छूटे नहीं। यदि हम हर वर्ग तक पहुंचेंगे, तो कोई कमजोर कड़ी नहीं रहेगी। उन्होंने प्रत्येक बस्ती में व्यक्ति-व्यक्ति से संपर्क करने पर जोर देते हुए कहा कि इस आयोजन को उत्सव का रूप दिया जाए। रामोत्सव की तरह बस्तियों में प्रभात फेरियां निकालने का सुझाव भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने-अपने मोहल्लों में उत्साह और आनंद का वातावरण तैयार किया जाए तथा बच्चों, महिलाओं और समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में खेड़ापति मंदिर के पुजारी संजय मिश्रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धार नगर के कार्यवाह गोपाल डोड भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर धार की सभी 14 बस्तियों के संयोजक एवं अन्य प्रमुख कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

पिपरिया विधायक की अनुशंसा पर 30 हितग्राहियों को 01 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। विधायक पिपरिया की अनुशंसा पर कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा स्वेच्छानुदान निधि से पिपरिया एवं बनखेडी के 30 हितग्राहियों को 01 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय नर्मदापुरम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक पिपरिया श्री ठाकुर दास नागवंशी की अनुशंसा पर पिपरिया एवं बनखेडी के 30 हितग्राहियों को क्रमश : 5-5 हजार रूपये कुल 01 लाख 50 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

सिवनीमालवा विधायक की अनुशंसा पर 05 निर्माण कार्य हेतु, 12 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। सिवनीमालवा विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा की अनुशंसा पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा में 05 निर्माण कार्य के लिए कुल 12 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवनीमालवा विधायक श्री वर्मा की अनुशंसा पर विधायक निधि से ग्राम-बघवाडा में सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे कक्ष निर्माण कार्य के लिए 04 लाख रूपये, ग्राम पंचायत झुनकर के ग्राम दौडी में श्री शंकर मंदिर के पास सार्वजनिक चौपाल एवं छत निर्माण कार्य के लिए 03 लाख 50 हजार, ग्राम पंचायत रजोराकुर्मी के ग्राम चबोरा में स्कूल के पास सार्वजनिक चबूतरे पर टीनसेट निर्माण कार्य के लिए 02 लाख 50 हजार रूपये, ग्राम पंचायत झुनकर के ग्राम दौडी स्कूल के पास छत चौपाल निर्माण कार्य के लिए 01 लाख 50 हजार रूपये तथा ग्राम पंचायत छीतापुरा तपसी बाबा के पास सार्वजनिक चबूतरे पर छत निर्माण कार्य के लिए 01 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

दोषी प्राचार्य, गार्ड और ड्राइवर को सेवा से पृथक करने का निर्देश सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर प्रशासन ने की कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। सोशल मीडिया में सीहोर तहसील के ग्राम जताखेड़ा स्थित सेंट मार्टिन स्कूल के छात्रों का फोटो प्रसारित होने पर जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए इस घटना की जांच कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह तोमर ने बताया कि यह फोटो दो माह पूर्व का है। उन्होंने बताया कि जांच में यह पाया गया कि होमवर्क नहीं करके आने पर बच्चों को प्रताड़ित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी श्री तोमर ने बताया कि स्कूल के संचालक को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को प्रताड़ित करने वाले स्कूल के प्रचार्य, गार्ड और ड्रायवर को तत्काल सेवा से पृथक किया जाये। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बच्चों और अभिभावकों से कहा गया है कि भविष्य में स्कूल में इस प्रकार की घटना होने पर स्थानीय पालक संघ एवं वरिष्ठ अधिकारियों या जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया जाये।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले में 527 गर्भवती महिलाओं की जांच

सीहोर (निप्र)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को जिले में गर्भवती महिलाओं को नि :शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की 09 एवं 25 तारीख को जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सेवाएं दी जाती हैं। अभियान के तहत आज कुल 527 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें से 176 महिलाओं को उच्च जोखिम वाली गर्भवती के रूप में चिन्हित किया गया। योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को नि :शुल्क जाँच, आवश्यक दवाइयाँ एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया, वहीं उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई। प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार की जटिल स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए नि :शुल्क पिकअप एवं ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें समय पर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

जेएच कॉलेज में एसडीईआरएफ ने दिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण

बैतूल (निप्र)। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं गृह विभाग मप्र शासन के निर्देशों के पालन में शासकीय जयवंती हॉक्सर कॉलेज में गुरुवार 26 दिसंबर को आपदा से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण प्लाटून कमाण्डर श्रीमती सुनीता पन्दरे के नेतृत्व में एसडीईआरएफ के जवानों द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जवानों ने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिले में संभावित बाढ़ आपदा, आग, भूकम्प, प्राथमिक उपचार तथा वर्तमान में चल रही शीतलहर से बचाव के उपायों को एक-एक कर समझाया गया।

प्राथमिक उपचार के अंतर्गत पट्टी बांधने, घायलों को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आकस्मिक विधियों की जानकारी दी गई। स्ट्रेचर के उपयोग के साथ-साथ घरेलू संसाधनों से स्ट्रेचर तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इसमें रस्सी, कंबल, बोरी, टी-शर्ट आदि से स्ट्रेचर बनाकर उसका उपयोग करना सिखाया गया। साथ ही आपात स्थिति में सीपीआर देने की विधि भी समझाई गई। बाढ़ आपदा के दौरान क्या करें और क्या न करें, इस पर विशेष जोर दिया गया। लाइफ जैकेट के उपयोग के साथ-साथ प्लास्टिक की बोतलों से अस्थायी लाइफ जैकेट बनाने तथा घरेलू सामान से राफ्ट तैयार करने की जानकारी दी गई। बांस की राफ्ट, कुंडी की राफ्ट, केले के तने, ढोलक, खाली ड्रम-पीपा, सूखी लकड़ियों के गट्ठे एवं चार पहिया वाहन के ट्यूब से राफ्ट बनाने के तरीके बताए गए।

भूकम्प को एक आकस्मिक आपदा बताते हुए इसके दौरान सावधानियों की जानकारी दी गई। वहीं आग लगने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, आग के प्रकार, गैस सिलेंडर में लगी आग बुझाने के तरीके, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगने पर कंबल से ढकने अथवा जमीन पर लेटकर गुलाटी करने की विधि समझाई गई। फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार, उनके उपयोग एवं सही तरीके से संचालन की जानकारी भी दी गई।

शीतलहर से बचाव के उपायों पर की चर्चा

ठंड के मौसम में शीतलहर से बचाव के उपायों पर भी चर्चा की गई। इसमें गरम कपड़े पहनने, सिर ढककर रखने, गरम भोजन एवं पेय पदार्थ का सेवन करने, आग जलाकर ठंड से बचने तथा बीमार होने पर तुरंत अस्पताल में उपचार कराने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी चौबे, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट श्री खुशहाल देवघरे, एनसीसी अधिकारी डॉ. ऋतु साहू, एनएसएस अधिकारी प्रोफेसर शंकर सातनकर सहित एनसीसी के लगभग 150 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अवैध मदिरा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, बड़ी मात्रा में देशी एवं विदेशी मदिरा जब्त

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता भोपाल श्री यशवंत धनोरा के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी श्री शरद पाठक के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती साधना पटेल के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी श्री पाठक ने बताया कि आज 26 दिसम्बर को वृत्त गंजबासोदा अंतर्गत मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर गंजबासोदा स्थित जैल रोड पर नरवरिया ढाबे पर विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी कमल सिंह नरवरिया पिता मिट्ठूलाल, उम्र 53 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, गंजबासोदा के कब्जे से कागज के 03 कार्टून देशी प्लेन मदिरा, 03 कार्टून देशी मसाला मदिरा एवं 01 कार्टून गोवा विदेशी मदिरा बरामद की गई। कुल 350 पाव मदिरा, जिसकी कुल मात्रा 63 बी.एल. है, जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।इसी प्रकार वृत्त गंजबासोदा के वार्ड क्रमांक 21 में एक मकान की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 22 पेटी देशी प्लेन, देशी मसाला एवं विदेशी मदिरा बरामद की गई।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय रायसेन का किया निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। रायसेन स्थित शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय का कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा शुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण कर शैक्षणिक कार्य और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों से अध्यापन कार्यप्रगति, कक्षावार बालिकाओं की संख्या तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले और प्रदेश की मेरिट सूची में विद्यालय की बालिकाएं स्थान प्राप्त करें, यह लक्ष्य निर्धारित कर प्रयास किए जाएं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर बालिकाओं से भी अध्यापन/शैक्षणिक कार्य की जानकारी ली। साथ ही अंग्रेजी विषय की पुस्तक से बालिकाओं से प्रश्न पूछे तथा एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री डीडी रजक भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिले में शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने तथा बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में वृद्धि हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिला अधिकारियों को प्रति सप्ताह शासकीय स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा स्वयं भी नियमित रूप से शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है।

विदिशा जिले में केंद्र एवं राज्य योजनाओं के अध्ययन हेतु केंद्र सरकार के अधिकारियों का अध्ययन भ्रमण

विदिशा (निप्र)। भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्था द्वारा संचालित स्टेट अटैच्ड ऑफिसर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार के छह अधिकारी कृ श्री मनीष कुमार, श्री शिवकुमार, श्री दिनेन्द्र कुमार, श्री वेदप्रकाश, श्री सुशील कुमार एवं श्री रामदास 26 से 30 दिसंबर तक विदिशा जिले के अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे हैं।

अध्ययन भ्रमण के दौरान अधिकारी जिले में क्रियान्वित विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का मैदानी स्तर पर अध्ययन, समीक्षा एवं मूल्यांकन करेंगे। इसी क्रम में आज द 26 दिसंबर को ग्राम पंचायत सुनपुरा के पंचायत भवन में योजनाओं के हितग्राहियों, संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद कर योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावशीलता की जानकारी ली गई।

आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोषण अभियान, सामाजिक न्याय सहित अन्य प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच, नवाचारों तथा सामने आ रही चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अध्ययन भ्रमण का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की वास्तविक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से समझना, सफल प्रयोगों एवं समस्याओं की पहचान करना तथा प्राप्त अनुभवों के आधार पर नीति निर्माण एवं प्रशासनिक सुधारों में सहयोग प्रदान करना है।

प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के भ्रमण के दौरान समन्वय एवं मार्गदर्शन हेतु जिला समन्वयक श्री राधेश्याम खंगार, परियोजना अधिकारी श्री संजय सिंह तथा एडीईओ श्री हेमंत धोटे उपस्थित रहे।

सहभागी नेतृत्व, विकेंद्रीकृत और पारदर्शी प्रशासन के उद्देश्य से छात्रा-पंचायत का आयोजन

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा में सहभागी नेतृत्व, विकेंद्रीकृत और पारदर्शी प्रशासन के उद्देश्य से छात्रा-पंचायत का आयोजन परंपरागत पंचायत प्रणाली के तर्ज पर किया गया, जिसमें एक तरफ महाविद्यालय की छात्राएं और दूसरी तरफ महाविद्यालय प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ जमीन पर बैठे थे।

इस आयोजन में प्राचार्य, प्राध्यापक, स्टाफ एवं छात्राओं ने मिल-बैठकर महाविद्यालय की समस्याओं पर चर्चा करते हुए महाविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए विचार-विमर्श किया। इस पंचायत में महाविद्यालय प्रशासन को लोकतांत्रिक स्वरूप देते हुए प्राचार्य ने छात्राओं को अपनी समस्याओं व सुझावों के साथ आमंत्रित किया।

एक घंटे के इस कार्यक्रम में छात्राओं ने लगभग बीस से अधिक समस्याओं को सामने रखा तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किए। छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न एवं उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का स्वयं प्राचार्य एवं संबंधित प्राध्यापकों के द्वारा उत्तर दिया गया तथा उठाई गई समस्याओं का मौके पर ही प्राचार्य द्वारा निराकरण किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ बी.डी. अहिरवार ने कहा कि छात्रा-पंचायत महाविद्यालय के वातावरण को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

महाविद्यालय का उत्थान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इसलिए एक सहभागी प्रशासनिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्राओं को अधिकतम सुविधाजनक वातावरण प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है। कार्यक्रम का संयोजन राजनीति विभाग के द्वारा किया गया, जिसका संचालन प्रो. रवि रंजन ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही एवं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। छात्रा पंचायत में खुले मंच पर अपनी बात रखकर छात्राएं उत्साहित दिखीं । पंचायत के समापन उपरांत छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में प्रताप प्रताप समूह बनाकर पूरे महाविद्यालय परिसर में श्रमदान भी किया।

नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। जिले में नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा जिले में नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूलों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों की भी जांच करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में नशीली दवाओं के दुरूपयोग के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को बंद पड़ी फैक्ट्रियों एवं कारखानों का भी सतत् निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिले में अफीम, भांग आदि की अवैध खेती की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु कृषि विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारियों को लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रेरणादायी एवं गरिमामय आयोजन हुआ

साहिबजादों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सत्य, साहस, राष्ट्रभक्ति और मानव मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति विनीता लोढ़ा के मार्गदर्शन में आज शुक्रवार को शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वीर बाल दिवस का आयोजन अत्यंत गरिमा, अनुशासन एवं उत्साह के साथ कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम मे विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति प्रति राकेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष श्री वीरसिंह रघुवंशी की उपस्थित रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा, सहायक संचालक श्री विवेक शर्मा, परियोजना अधिकारी श्री संजय सिंह, श्री अरविन्द मिश्रा श्री संतोष रघुवंशी सहित जिले के 20 पर्यवेक्षक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वागत किया गया।

कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि यह रही कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजुअल माध्यम से देश एवं विदिशा के बच्चों को संबोधित किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन और शहादत आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे साहिबजादों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सत्य, साहस, राष्ट्रभक्ति और मानव मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें। उल्लेखनीय है कि 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा स्मरण रखा जा सके और उनकी वीर गाथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रेरणा देती रहे।

वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जैसे महापुरुषों की ड्रेस कम्पटीशन, देश भक्ति गीत, ड्राइंग कम्पटीशन, निबंध एवं बाद विबाद प्रतियोगिता इन गतिविधियों का उद्देश्य विशेषकर बच्चों और युवाओं को साहिबजादों के बलिदान एवं भारतीय इतिहास के युवा नायकों की वीरता से परिचित कराना है। इन कार्यक्रमों में कथा वाचन, कविता पाठ, पोस्टर निर्माण, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं। ये गतिविधियां विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा माई गव और माई भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी आयोजित की गईं हैं। विभिन्न गतिविधि मे भाग लेने बाले बच्चों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुरुस्कार वितरित किये गये।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें साहिबजादों के जीवन, त्याग और वीरता का भावपूर्ण चित्रण किया गया। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा आयोजन में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

राइट क्लिक

खनन पर सौ फीसदी रोक से ही बच सकेगा अरावली

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

देश की राजधानी दिल्ली और पश्चिमी भारत की पर्यावरण ढाल कही जाने वाली अरावली पर्वत माला में नए खनन पर केन्द्र सरकार ने पर्यावरणप्रेमियों के भारी विरोध के चलते अभी भले ही रोक दिया हो, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे भी अहम मुद्दा उन खदानों का है, जो वहां अभी चल रही हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में ऐसी 1008 खदानें चल रही हैं। सरकार ने इनके बारे में सिर्फ इतना कहा है कि इन पर पर्यावरण सख्तीस और बढ़ेगी। जबकि सामान्य अनुभव तो यह है कि वैध खदान से कई गुना ज्यादा खनन तो अवैध तरीके से होता है। जब तक अरावली में खनन पर सौ फीसदी रोक नहीं लगती तब तक 'दिल्ली के इन फेंफड़ों' को बचाने की बात कागजी ज्यादा है।

अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व बनी हैं। यह ऋषि पराशर की तपोभूमि है और महर्षि वेद व्यास का जन्म भी यहीं हुआ माना जाता है। हिमालय से भी प्राचीन यह पर्वत श्रृंखला 692 किमी लंबी है और पांच राज्यों से होकर गुजरती है। इसका अस्सी फीसदी हिस्सा राजस्थान में है। इतने सालों से शान से खड़ी यह पर्वत मामला 21 सदी के आते-आते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। ताजा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें उसने पहाड़ियों की केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की 'वैज्ञानिक परिभाषा' को मंजूरी दी। विगत 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस आदेश से सिर्फ राजस्थान के 15 जिलों में 20 मीटर से ऊंची 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 (8.7 फीसदी) ही इस मानक को पूरा कर सकेंगी और 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। यानी इस इलाके में खनन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरावली को बचाने को लेकर 1000 किलोमीटर लंबी अरावली आंदोलन जनयात्रा माउंट आबू में शुरू हुई। ग्रीनमैन नरपतसिंह राजपुरोहित ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम लिखा ज्ञापन बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी दिया और 'अरावली बचाओ' जैसे स्लोगन भी लिखे।

बहरहाल मोदी सरकार ने अरावली से नई छेड़छाड़ पर रोक लगाकर संवेदनशीलता दिखाई है। सरकार दबाव में इसलिए आई क्योंकि आम लोगों के विरोध के साथ-साथ यह राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा था। वरना एक हफ्ते पहले तो केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव अरावली में खनन को जायज बताते हुए कह रहे थे कि वहां केवल 277. 89 वर्ग किमी में ही खनन की अनुमति दी गई है, जो अरावली पर्वतमाला के कुल क्षेत्र 1 लाख 43 हजार 577 वर्ग किमी का महज 0.19 फीसदी है। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार खनन को बढ़ावा देने की अपनी मंशा को आंकड़ों में छिपाना चाहती है?

पूर्व में इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2005 के आदेश के बाद अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टे देने पर रोक है, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। क्योंकि खनन गतिविधियों से 8 लाख लोगों को सीधे और 20 से 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। कोर्ट के प्रतिबंधों से लगभग 10 हजार औद्योगिक इकाइयां भी प्रभावित हुई हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। ये इकाइयां अरावली क्षेत्र वाले 16 जिलों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं।

यह तर्क अपनी जगह है, लेकिन लोगों के रोजगार की चिंता किस कीमत पर की जा रही है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि केन्द्र सरकार ने कहा है कि अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि सरकार अरावली की 'परिभाषा' बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। रमेश के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और न्याय मित्र ने इस नई परिभाषा का विरोध किया था। फिर भी सरकार इसे क्यों थोप रही है? इस पर केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस 'गलत सूचना' फैला रही है। अरावली के केवल 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन हो रहा है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि केन्द्रीय सशक्त समिति (सीईसी) के वर्ष 2024 के दस्तावेज में राजस्थान सरकार के ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट-2047 का उल्लेख है, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास के लिए अरावली में खनन क्षेत्र 2,339 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 4,000 वर्ग किलोमीटर करने की योजना है। जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिस 277.9 वर्ग किमी में खनन की बात कही थी, वह संशोधित परिभाषा है। बहरहाल विवाद की असली जड़ यह है कि 'अरावली' किसे माना जाए? विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिभाषा बदलकर अरावली का दायरा कम कर रही है ताकि बाकी जगहों पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा सके, जबकि सरकार इसे संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। गौरतलब है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर-पश्चिम भारत का 'फेफड़ा' और 'दीवार' माना जाता है। यह दीवार थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर (दिल्ली और यूपी) बढ़ने से रोकती है और भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है। दिल्ली-एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि जीवनरक्षक संसाधनों का भी खजाना है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अरावली पर्वतमाला खत्म हुई तो भविष्य में दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है।

इस बीच केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जब तक अरावली की वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती, वहां खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मकसद अरावली को एक 'निरंतर भूवैज्ञानिक रिज' के रूप में बचाना है। पर्यावरण मंत्रालय ने 'इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन' (आईसीएफआरई) को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जहां खनन पूरी तरह वर्जित होगा। यह काम क्षेत्र की यह काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आईसीएफआरई एक व्यापक और वैज्ञानिक 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' तैयार करेगा। जिसमें यह देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें।

इसी दौरान हरियाणा वन विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी आर.पी.बलवान ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति द्वारा 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यह तकनीकी मुद्दा न होकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के पर्यावरणीय भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इस पर सुनवाई 7 जनवरी को होना है। उल्लेखनीय है कि डॉ. बलवान 'द अरावली इको सिस्टम मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन' पुस्तक के लेखक भी हैं। वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरावली की 31 पहाड़ियां खनन से खत्म हो चुकी हैं। इस कमेटी ने राजस्थान के 15 जिलों को खनन से प्रभावित बताया था। पर्यावरण नुकसान को धता बताते हुए खनन से हर साल करीब 5000 करोड़ की रॉयल्टी विभिन्न माइनिंग कंपनियों को मिलती है।

दरअसल अरावली में खनन को लेकर कोई एक स्पष्ट नियम या फॉर्मूला नहीं है। लिहाजा मिलीभगत कर पहाड़ों को खोदा जा रहा है। सम्बन्धित राज्य इन पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा अपने-अपने तरीके से तय कर रहे हैं। 'पीपल फ़ॉर अरावलीज़' समूह की संस्थापक सदस्य नीलम अहलूवालिया के अनुसार अरावली को सिर्फ़ ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यह मान लेना ग़लत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर ज़मीन पर खनन की इजाज़त होगी। लेकिन सबको पता है कि देश में खनन लॉबी कितनी ताकतवर है।

यूं अवैध खनन तो देश में तकरीबन हर राज्य में धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन वैध खनन में भी पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार कर तात्कालिक लाभों को और लूट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आलम यह है कि तमाम पहाड़ और पहाड़ियों कर खनन के अंधाधुंध पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जिससे कई इलाकों में पहाड़ियों का वजूद ही खत्म हो गया है। मप्र में इंदौर-भोपाल राजमार्ग इसका गवाह है, जहां देवास क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां बेतहाशा खनन के चलते समतल में बदल गई हैं। जंगलों की कहानी तो इससे भी बदतर है।

इसके पहले हम मुंबई का 1200 एकड़ का आरे जंगल, उत्तराखंड के कटते जंगल और बांधों, ऑल-वेदर सड़कों और पर्यटन प्रोजेक्ट्स के कारण हिमालय को खोखला होते देख चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 25 वर्षों में 50 हजार हेक्टेयर जंगल नष्ट हो चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में 612.41 वर्ग किमी की कमी आई है, जो देश में सर्वाधिक है। कई नदियां प्रदूषित हैं और दुनिया में सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले पश्चिमी घाट पर खनन की मार है। अंडमान निकोबार में वर्षावन कट रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा की प्राकृतिक ढाल भी कमजोर होती जा रही है।

यहां बात केवल अरावली की ही नहीं है, खतरा देश की उन सात विशाल पर्वतमालाओं पर भी है, जो भारत के पर्यावरण और मौसम को नियंत्रित करती हैं। सवाल यह है कि क्या अब खोदने के लिए हमारे प्राकृतिक रक्षक पर्वत ही बाकी रह गए हैं? जंगलों को तो हमने बर्बाद कर ही दिया है, नदियों का भी बुरा हाल है। जब ये सब बचेंगे ही नहीं तो हम जीएंगे किसके लिए और कैसे? विकास के नाम पर पृथ्वील के गर्भ को खोखला कर डालने का इंसानी जुनून आखिर हमे कहां ले जाकर छोड़ेगा?

दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में इंदौर का 'आरईटी' मॉडल

इंदौर का 'आरईटी' मॉडल एक अभिनव संरक्षण परियोजना है, जिसे वन विभाग ने शुरू किया। इसमें दुर्लभ, लुप्तप्राय और खतरे वाली 58 से अधिक स्थानीय वृक्ष प्रजातियां (जैसे तेंदू, करंज, अर्जुन और सालिपर आदि) को बचाने और उनका पुनर्जन्म कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह प्रयोग इसलिए लिया गया कि जंगलों की जैव विविधता और आनुवंशिक विविधता को बहाल किया जा सके। यह मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफल होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

पर्यावरण

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' इंदौर के स्थानीय संपादक है।

इंदौर शहर अपनी स्वच्छता, स्वादिष्ट व्यंजनों और ऐसे ही कुछ नवाचारों के लिए हमेशा देशभर में चर्चा में रहता है। लेकिन, अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी यह शहर ने एक नई मिसाल कायम करने की दिशा में काम कर रहा है। इंदौर के 'आरईटी' मॉडल की चर्चा है, जो उन दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त वनस्पतियों के संरक्षण का देश में पहला संगठित और दोहराने योग्य प्रयास है। यह मॉडल सिर्फ सौंदर्यवर्धक नहीं, बल्कि जैव विविधता की रक्षा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना का अभिनव उदाहरण है। पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अनियंत्रित भूमि उपयोग ने भारतीय जैव विविधता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। कई ऐसी औषधीय व स्थानीय पौधों की प्रजातियां जो पहले गांवों और जंगलों में सहज ही मिल जाती थी, अब 'विलुप्तप्राय' सूची में दर्ज हो चुकी हैं।

इसके परिणामस्वरूप, पारंपरिक ज्ञान जैसे लोक औषधि, कृषि आधारित पारिस्थितिकी और प्राकृतिक परागण व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। इस पृष्ठभूमि में इंदौर का आरईटी मॉडल न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी गहन मायने रखता है। आरईटी मॉडल से आशय है दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त यानी ऐसी वनस्पतियां जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वन विभाग के जिला अधिकारी (डीएफओ) प्रदीप मिश्रा ने बॉटनिकल विशेषज्ञों के सहयोग से इन पौधों की पहचान कर उनका संरक्षण सुनिश्चित करने की एक व्यवस्थित योजना तैयार की। इस परियोजना में न केवल पौधों की पहचान और रोपण शामिल है, बल्कि प्राकृतिक आवास जैसा परिवेश तैयार कर उन्हें पुनर्विकसित करने की दीर्घकालिक रणनीति भी जोड़ी गई है।

इस मॉडल की प्रमुख विशेषताओं में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आधारित चयन शामिल है। परियोजना में सबसे पहले वनस्पतियों की जीव वैज्ञानिक स्थिति का सर्वेक्षण किया गया। विशेषज्ञों ने ऐसे पौधों की सूची बनाई, जो मध्य भारत या मालवा क्षेत्र में विलुप्ति के कगार पर हैं, जैसे सर्फुंका, सफेद सर्पगंधा, अपराजिता, वासा, अश्वगंधा, अर्जुन और गोखरू जैसी औषधीय प्रजातियां। इन प्रजातियों के बीजों को लैब में संरक्षित किया गया और नियंत्रित परिवेश में पौध तैयार करने का काम किया गया। 'आरईटी' नर्सरी को इस प्रकार विकसित किया गया कि यह प्राकृतिक परिस्थितियों का अनुसरण करती है, जिससे पौधे जीवित रहने की क्षमता विकसित कर सकें।

प्रदीप मिश्रा के मुताबिक, इंदौर शहर के भीतर और आसपास ऐसे 'आरईटी गार्डन' तैयार किए गए हैं, जहां इन पौधों को उनके अनुकूल मिट्टी, जलवायु और जैविक परिस्थितियों में लगाया गया। यह पार्क आम लोगों के लिए अध्ययन और जागरूकता का केंद्र भी बन रहे हैं। इस मॉडल ने शहरी हरियाली को केवल सजावटी पौधों से आगे ले जाकर स्थानीय पारिस्थितिकी संरक्षण से जोड़ा। यानी अब हर पार्क, ग्रीन बेल्ट या सरकारी परिसर में लगाए जाने वाले पौधों में 'आरईटी' प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है। निश्चित रूप से यह आसान मिशन नहीं है। इसके लिए जनता की सहभागिता और उसके बारे में शिक्षा भी जरूरी है। स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और पर्यावरण संगठनों को इस अभियान से जोड़ा गया, ताकि नागरिकों में संरक्षण की समझ बढ़े। औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग पर कार्यशाला आयोजित की जा रही हैं।

इंदौर का 'आरईटी' मॉडल अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे। स्थानीय पर्यावरण में 60 से अधिक लुप्तप्राय प्रजातियों का पुनर्रोपण किया गया है। कई पौधों ने प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन करना शुरू किया है, जिससे बीज फैलाव और जैव विविधता पुनर्स्थापना में मदद मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में मधुमक्खियों और परागण करने वाले कीड़ों की बढ़ती गतिविधि देखी गई, जो पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। स्थानीय हर्बलिस्ट और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों को भी इन पौधों के संरक्षण से लाभ हुआ है, जिससे पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को नया सहारा मिला है।

डीएफओ बताते हैं कि इस मिशन से राष्ट्रीय महत्व और पुनरावृत्ति की संभावना है। खास बात यह भी कि इंदौर का यह 'आरईटी' मॉडल सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा। पर्यावरण मंत्रालय और अन्य नगर निगमों भी इसे 'रीप्लिकेबल मॉडल' के रूप में देख रहे हैं। यानी इसे देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कई नगर निकाय इस मॉडल को समझने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इससे देश भर में पौध विविधता के पुनरुद्धार का रास्ता खुल सकता है। स्थानीय भावना और सांस्कृतिक जुड़ाव मालवा क्षेत्र की पहचान सिर्फ कृषि या खान-पान से नहीं, बल्कि उसके लोक औषधि और प्राकृतिक ज्ञान से भी है। यहां आदिवासी और ग्रामीण समाज पीढ़ियों से वनस्पतियों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को संजोकर रखते आए हैं।

प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि 'आरईटी' मॉडल में लोक परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना इस पहल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह सिर्फ पौधे बचाने की नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की परियोजना भी है। अब इस मॉडल को डिजिटाइज किया जा रहा है। हर पौधे का जीपीएस टैग, डेटाबेस रिकॉर्ड और ग्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार हो रहा है। इससे भविष्य में डेटा आधारित नीति निर्माण और वनस्पति प्रबंधन में मदद मिलेगी। यदि यह प्रयोग अपने पूर्ण स्वरूप में सफल होता है, तो इंदौर न केवल स्वच्छता बल्कि पर्यावरणीय स्थायित्व और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भी देश के लिए प्रेरणा बनेगा। इंदौर का यह अनोखा मॉडल यह सिखाता है, कि संरक्षण केवल जंगलों या पहाड़ियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। शहरों, जहाँ सबसे अधिक पर्यावरणीय दबाव है, वहीं से यदि ऐसा आंदोलन शुरू हो, तो यह पूरे देश के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है।यह मॉडल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनेगा, जहां विज्ञान, परंपरा और नागरिक सहभागिता मिलकर भारत की हरियाली को पुनः जीवित कर रहे हैं।

कही-सुनी

रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम कब होगा लागू

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

चर्चा थी कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम एक जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक की तैयारियों को देखकर लगता नहीं है कि एक जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नर की ताजपोशी हो पाएगी। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा का अब तक प्रस्ताव नहीं है और न ही मंत्री स्तर पर कोई चर्चा हो पाई है। खबर है कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर गृह मंत्री विजय शर्मा इस हफ्ते मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मुख्य सचिव के चीफ सेक्रेटरी कांफ्रेस में दिल्ली चले जाने से मामला टल गया। बताते हैं रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए ओड़िशा,महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश और अन्य कुछ राज्यों के पुलिस कमिश्नर सिस्टम का अध्ययन किया गया है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। इस कारण विधेयक का प्रारूप भी नहीं बनाया जा सका है। अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए विधेयक लाया जाएगा या अध्यादेश यह भी तय नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मामला 26 जनवरी तक तो टल ही गया। पर सब कुछ सरकार के रुख पर निर्भर करेगा।

जमाना बाबाओं का

कहा जा रहा है यह जमाना तो बाबाओं का ही है। बाबा बन जाओ वारे-न्यारे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो बाबाओं की और भी इज्जत है। यहां बाबाओं को राजकीय अतिथि का दर्जा मिल जाता है और उनकी सेवा में सरकारी उड़नखटोला भी पेश कर दिया जाता है। यहां मंत्री उनकी सेवा में हाजिर होते हैं और कानून के रखवाले चरण वंदना करते हैं। शायद ऐसा माकूल जगह देश में कहीं और नहीं मिलता इस कारण कई बाबा लोग छत्तीसगढ़ में मंडराते नजर आते हैं और अच्छी फसल काटकर ले जाते हैं। बाबाओं के दरबार में बड़े-बड़े राजनेता शीश नवाने पहुंच जाते हैं और कई छुटभैय्ये नेता बाबाओं के दरबार सजवाकर ओहदेदार और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। बाबाओं का दरबार सजवाने वाला एक व्यक्ति तो अपने को इतना ऊँचा मान लिया कि विधायकों को अपनी जेब में रखने की बात करने लगा। अब एक बाबा के सत्कार को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा के लोग एक-दूसरे पर वार-प्रतिवार कर रहे हैं। बाबाओं को लेकर भले राजनीतिक खींचतान चले, लोग बाबा की तरफ खींचे चले जाएंगे तो दरबार सजाने वाले मौका का फायदा उठाएंगे ही। बाबाओं के दरबार भीड़ जुटाने और ताकत दिखाने का अच्छा माध्यम बन गया है, सो हर कोई फसल काटना चाहता है। यह सही भी जमाना तो बाबाओं का ही, इसलिए नए-नए बाबा पैदा हो रहे हैं।

महिला आईएएस का टेरर

आजकल मंत्रालय महानदी भवन में एक महिला आईएएस अफसर का टेरर चर्चा में है। कहते हैं महिला आईएएस ने अपने मातहत अफसर को ऐसी फटकार लगाई की, वह जीवन से ही उबने लग गया। बताते हैं महिला अफसर अपने को बहुत ईमानदार बताती हैं और अपने मातहतों के बीच ईमानदारी की बखान भी करती हैं। महिला अफसर के रुख से मातहतों में घबराहट बनी रहती है। सुनते हैं कि महिला अफसर अपने मातहत महिला अफसरों को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकतीं। कुछ साल पहले अपने मातहत महिला अफसर के पहनावे को लेकर भड़क गईं थी और खरी-खरी सुना दी थी। महिला अफसर ने एक मीटिंग में अपने से कनिष्ठ अफसर को आड़े हाथों ले लिया था। कहा जाता है सीनियर महिला अफसर कब किस पर भड़क जायं, पता नहीं होता। सब कुछ उनके मूड पर निर्भर करता है।

नए साल में प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें

चर्चा है कि नए साल के पहले या दूसरे हफ्ते में मंत्रालय और जिला स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। कहा जा रहा है कि नए साल में दो-तीन जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। मंत्रालय में भी सचिव स्तर के कई अफसरों के विभागों में हेरफेर हो सकता है। कुछ अफसर दो साल से अधिक समय से एक ही विभाग में तैनात हैं, उनको बदले जाने की चर्चा है। समग्र शिक्षा की आयुक्त डॉ प्रियंका शुक्ला के प्रतिनियुक्ति पर जाने से रिक्त पद पर भी सरकार को किसी की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ अफसर केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं।

अजय चंद्राकर के तीखे तेवर के मायने

डॉ रमन सिंह के मंत्रिमंडल में 10 साल मंत्री रहे कुरुद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर विधानसभा के भीतर लगातार तीखे तेवर दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में अजय चंद्राकर के सवालों से कई मौकों पर मंत्री पसोपेश में दिखे। अजय चंद्राकर वरिष्ठ और अनुभवी विधायक हैं, उनके मुकाबले जूनियर विधायक साय सरकार में मंत्री बन गए हैं। अजय चंद्राकर स्वाभाविक रूप से मंत्री की दौड़ में थे, पर नए फार्मूले में कुर्मी वर्ग से टंकराम वर्मा मंत्री बन गए। वैसे तो अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, लता उसेंडी,विक्रम उसेंडी जैसे पुराने मंत्रियों को भी साय कैबिनेट में जगह नहीं मिली। केदार कश्यप, रामविचार नेताम और दयालदास बघेल किस्मत वाले निकले। भाजपा की नई रणनीति को देखते हुए लोग चर्चा कर रहे हैं कि पुराने नेताओं का समय लौटने की संभावना कम ही है।

रायपुर की साख पर बट्टा

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ बंद के दौरान एक शॉपिंग माल में कुछ लोगों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, उससे देश-दुनिया में रायपुर की बदनामी हो गई है। यह घटना सुर्खियों में है। कुछ लोग अपना हित साधने के लिए ऐसे काम कर जाते हैं, जिससे समाज बदनाम होता है और घाव भी इतना गहरा हो जाता है कि उसका सालों भरना संभव नहीं होता। अब रायपुर की पुलिस शॉपिंग माल में घटना को अंजाम देने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी से रायपुर की साख पर लगा दाग इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है।